

//-- सुविचार --//

कभी भी बड़ी योजना का हिसाब मत लगाओ, धीरे धीरे शुरू करो, अपनी जमीन बनाओ और धीरे-धीरे उसे बढ़ाओ

सूर्योदय/सूर्यास्त

उदय : 05:15 प्रातः
अस्त : 06:36 संध्या

प्रदेश का तापमान

स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
रांची	28.0	24.0
जमशेदपुर	29.0	25.0
हजारीबाग	30.0	24.0
डालटनगंज	32.0	26.0

संक्षिप्त खबरें

गतिरोध खत्म करने की कोशिश, सरकार बुला सकती है सर्वदलीय पल्लोर लीडर्स की बैठक

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में पिछले चार दिनों से गतिरोध जारी है। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष में टकराव के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई है। संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक मामले पर जारी गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के पल्लोर लीडर्स की बैठक बुला सकती है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के लगातार विशेष और हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सभी दलों के पल्लोर लीडर्स से अपील की कि वे चर्चा की अवधि और नियमों पर सहमति बनाएं, ताकि सदन में सार्थक बहस हो सके। सरकार की इस पहल का उद्देश्य संसद में जारी गतिरोध समाप्त करना और नीट पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा का रास्ता साफ करना है।

भड़की आंदोलन की आग. कल भाजपाइयों ने घेरा था कांग्रेस कार्यालय, अब भाजपा ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

दोनों ओर से टमाटर-अंडे फेंके गये, पत्थरबाजी, कई घायल

प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता

नव प्रदेश संवाददाता

रांची। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के निकट प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भीड़ गए। टमाटर और अंडा फेंकने के बाद पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस दौरान कई मीडियाकर्मियों को भी चोटें लगने की खबर है। मालूम हो कि इसके एक दिन पूर्व बुधवार को भाजपा नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर वहां प्रदर्शन किया था।

दोनों ओर से टमाटर और अंडा फेंकने के साथ पत्थरबाजी

प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अग्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर वाटर कैनन, अमिशनम वाहन और अन्य सुरक्षा संसाधन तैनात किए



रांची : बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, चले पत्थर

गए थे। इसके बावजूद दोनों ओर से टमाटर और अंडा फेंकने की घटना हुई। इसके बाद पत्थरबाजी की घटना भी हुई। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते

कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक डायवर्ट

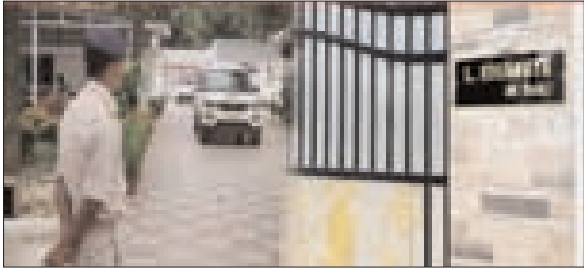
दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। साथ ही कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया।

कांग्रेस कार्यालय के घेराव के विरोध में शक्ति प्रदर्शन

इससे पहले बुधवार को भाजपा ने जेपीएससी में कथित भर्ती घोटालों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया था। अब इसके जवाब में कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय और उसके आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बीजेपी कार्यालय परिसर के बाहर और आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल, रैपिड रिसांस टीम और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गयी थी।

जेपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच तेज

पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते के घर सीआईडी का छापा



रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी की जांच अब पूर्व अध्यक्ष तक पहुंच गई है। गुरुवार को अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की टीम जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके एल खियांग्ते के आवास पर पहुंची। टीम ने उनके घर की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में पहले भी कई स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है और महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं, अब जांच की कड़ी पूर्व अध्यक्ष के आवास तक पहुंचने को इस मामले में अहम कदम माना जा रहा है। इस मामले में सीआईडी अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें जेपीएससी की तत्कालीन डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता, टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रामवीर सिंह, कंपनी के कर्मचारी प्रशांत कुमार, अभिषेक कुमार और अजय कुमार शामिल हैं। जांच एजेंसी ने उनके पास से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।

सीआईडी की कार्रवाई के बाद 22 जुलाई को जेपीएससी ने 25 जुलाई से प्रस्तावित 14वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। इसके लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया था। उल्लेखनीय है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम को लेकर अमर्षयियों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी थी। जांच के दौरान लगातार हो रही गिरफ्तारियों और अब पूर्व चेयरमैन के आवास पर हुई तलाशी से साफ है कि एजेंसी मामले की हर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

छात्रों के समर्थन में भाजपा के दिग्गज नेता, बोले-

लड़कियों पर बल प्रयोग देखकर पीड़ा हुई : मुरली मनोहर जोशी

नई दिल्ली। धर्मेद प्रधान का इस्तीफा मांग रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के छात्रों के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। मुरली मनोहर जोशी ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और खासतौर पर महिलाओं पर बल प्रयोग होता देखना पीड़ा दायक है।

छात्रों की चिंता को बताया जायज

मुरली मनोहर जोशी ने लिखा-यह देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के अलग-अलग भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी



और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, जिससे बलपूर्वक निपटा जाये। मुझे यह देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्भम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।

अभावपि ने भी जलाया धर्मेद प्रधान का पुतला

उपर, भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने भी आज छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक के खिलाफ उतराखंड के मसुरी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को धर्मेद प्रधान का इस्तीफा मांगा। केंद्र सरकार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धर्मेद प्रधान का पुतला जलाया।

राहुल गांधी बस से पहुंचे, गांधी स्मृति पहुंचा विपक्ष

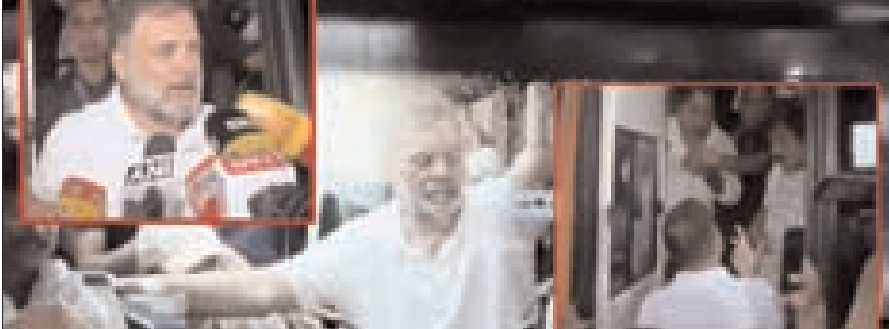
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर सिवासी तापमान और बढ़ गया है। गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद एकजुट होकर गांधी स्मृति पहुंचे। राहुल गांधी अपने सरकारी आवास से विपक्षी नेताओं के साथ एक बस में सवार होकर निकले। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई(एम) समेत कई विपक्षी दलों के सांसद उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि, यात्रा शुरू होने से पहले कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ मिनट तक चली बातचीत के बाद पुलिस ने रास्ता खोल दिया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं का काफिला गांधी स्मृति के लिए रवाना हो गया।

'छात्र सड़क पर हैं, इसलिए हम भी सड़क पर हैं'

रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ा रहे। उन्होंने कहा, 'हम पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद हमने गांधी स्मृति जाने का फैसला किया, वहां भी हमें कुछ देर रोकना पड़ा। हमारा सबसे बड़ा संदेश देश के छात्रों के लिए है कि हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे।'

पहले हुई रणनीति बैठक, फिर निकला विपक्ष का काफिला

गांधी स्मृति मार्च से पहले राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी



लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ा रहे। उन्होंने कहा, 'हम पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद हमने गांधी स्मृति जाने का फैसला किया। बैठक की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।

विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देशभर में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन

इस्तीफा दें। नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की जवाबदेही तय की जाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर सरकार से जवाब लिया जाए।

क्यों निकाली गई यह बस यात्रा

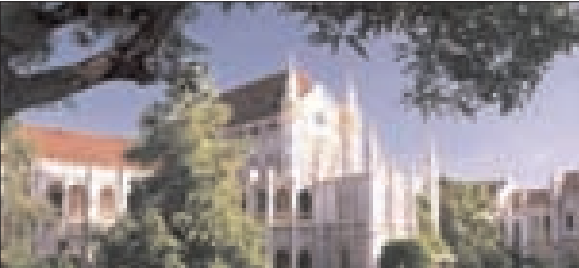
विपक्षी दलों का कहना है कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के समर्थन का संदेश है जो नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों से प्रभावित हुए हैं। गांधी स्मृति पहुंचकर नेताओं ने छात्रों के संघर्ष के प्रति एकजुटता जताने, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाने और छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि देने का संदेश दिया। साथ ही पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों और आंदोलनरत युवाओं के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया।

अंतरराज्यीय अपराध साइबर ठगी की जांच में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, केन्द्र के दो सचिव तलब

झारखंड समेत तीन राज्यों के डीजीपी जबलपुर हाइकोर्ट में तलब

जबलपुर। जबलपुर में छह लाख रुपये की कथित साइबर ठगी के मामले में पुलिस-प्रशासन की सुस्त कार्रवाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की जांच में हो रही देरी पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड के पुलिस महानिदेशकों, संबंधित राज्यों के गृह सचिवों, केंद्र सरकार के गृह सचिव, दूरसंचार विभाग के केंद्रीय सचिव, जबलपुर पुलिस अधीक्षक तथा मामले से जुड़े जांच अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि जांच में देरी से न केवल विवेचना प्रभावित होती है, बल्कि आरोपियों को ठगी की रकम ठिकाने लगाने का भी मौका मिल जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक



(फ्हक) को यह बताना चाहिए कि साइबर फ्रॉड की जांच के दौरान बैंकों द्वारा समय पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से नियामकीय सुरक्षा उपाय लागू हैं। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन इस मामले में गंभीर संस्थागत कमियों को उजागर किया है। विभिन्न राज्यों की पुलिस, जांच एजेंसियों और बैंकिंग संस्थानों के बीच, साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच

जानकारी तेजी से साझा करें और संहिध लेनदेन की रिपोर्ट करें। लेकिन अक्सर बैंक आवश्यक तत्परता नहीं दिखाते। धोखाधड़ी के बाद बीतने वाला हर घंटा पीड़ित की रकम वापस मिलने की संभावना को कम कर देता है।

एकलपीठ ने कहा कि आरोपी इसी समन्वय की कमी का लाभ उठाते हैं। तकनीक ने अपराधियों को राज्य की सीमाओं से परे आसानी से अपराध करने में सक्षम बना दिया है, जबकि जांच एजेंसियां अब भी प्रशासनिक सीमाओं में बंधी हुई हैं। साइबर अपराध अब केवल राज्य का विषय नहीं रह गया है। इसके लिए राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां, बैंकिंग संस्थानों, वित्तीय नियामकों और दूरसंचार विभाग के बीच निबंध सहयोग आवश्यक है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब 'प्रतिम और पेड्रो' के एक साथ आने का समय है। साइबर अपराध की प्रभावी जांच तभी

संभव है, जब तकनीकी विशेषज्ञता और पारंपरिक पुलिसिंग पूरी तत्परता और समन्वय के साथ काम करें। साइबर अपराधी क्षेत्रीय सीमाओं से परे काम करते हैं, जबकि जांच एजेंसियां अब भी प्रशासनिक दायरों में सीमित हैं। यह व्यवस्था न तो प्रभावी है और न ही टिकाऊ। इसलिए न्यायालय ने कहा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए एक केंद्रीकृत, तकनीक-सक्षम और समयबद्ध प्रोटोकॉल तैयार करने हेतु राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, बैंकिंग नियामकों, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार प्राधिकरणों और जांच एजेंसियों के बीच संयुक्त विचार-विमर्श आवश्यक है। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता, प्रतिवादिनों, न्याय मित्र और अधिवक्ताओं से इस संबंध में टोस सुझाव देने का अनुरोध किया है, ताकि साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक प्रभावी संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके।

सीजेपी ने आज देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध का किया आह्वान

नई दिल्ली। सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सभी से शुक्रवार को देश के हर जिले में एक दिन के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इसका मुख्य उद्देश्य हर जिला, एक दिन, एक मांग के संदेश के तहत पूरे देश में एकजुटता प्रदर्शित करना है। सीजेपी के मुताबिक, यह प्रदर्शन देशभर में कथित पुलिस बर्बरता के शिकार पीड़ितों के समर्थन में होगा। आरोपकों ने देश के विभिन्न छात्र सवों और अन्य सामाजिक संगठनों से इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने, आवश्यक अनुमतियां लेने और लॉजिस्टिक्स जुटाने की अपील की है। इस दौरान, विरोध स्थल पर एकत्र भीड़ के सामने छात्रों की मांगों को प्रमुखता से पढ़ा जाएगा। पुलिस कार्रवाई और बर्बरता का सामना करने वाले लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता जताई जाएगी। उल्लेखनीय है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रही सीजेपी ने 'संसद चलो मार्च' की घोषणा की थी जिसके बाद 20 जुलाई को हजारों की संख्या में एकजुट हुए छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया था। वे शिक्षा प्रणाली में अनियमितताओं और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन 26वें दिन भी जारी, हालत स्थिर

गुरुग्राम। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद अनशन गुरुवार को 26वें दिन भी जारी रहा। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है और सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं। गुरुवार शाम को अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. संजय दुरानी की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि सोनम की स्वास्थ्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। वह स्टेबल और अलर्ट हैं। पूरी तरह से होश में हैं। उनके सभी वाइटल पैरामीटर सामान्य सीमा में हैं। वांगचुक का इलाज उनकी सूचित सहमति के अनुसार जारी है। उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक को 21 जुलाई की शाम हाईकोर्ट के आदेश पर मेदांता



अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अस्पताल में उनकी सुरक्षा के लिए श्री-लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और करीब 600 जवान तैनात हैं। वांगचुक द्वारा लिखा गया ओपन लेटर सार्वजनिक होने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से उनसे कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया था कि जल्दी उस लेटर का जवाब देंगे। डॉक्टरों की निगरानी में वांगचुक का उपचार जारी है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

मंत्री इरफान ने नीट में सफल छात्रों को सम्मानित किया

रांची। गोल इंस्टीट्यूट की ओर से गुरुवार को रांची में नीट में सफल छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इंस्टीच्यूट से नीट परीक्षा 2026 में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है, लेकिन उनका मन उन लाखों छात्रों के दर्द से भी व्यथित है। जिनके सपनों पर पेपर लोक की घटनाओं ने चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि 28 वर्षों की अपनी गौरवशाली यात्रा में गोल इंस्टीट्यूट के18,000 विद्यार्थी नीट परीक्षा में सफल होकर आज भारत और विदेशों में चिकित्सक के रूप में मानवता की सेवा कर रहे हैं। यह किसी भी संस्थान के लिए असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के नीट परिणामों में गोल इंस्टीट्यूट का प्रदर्शन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है। मंत्री ने कहा कि पेपर लोक जैसी घटनाओं के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सफलता से वंचित रह गए। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रभावी पहल करे, ताकि मेहनत करने वाले किसी भी विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद न हो। अंसारी ने कहा कि वे छात्रों और अभिभावकों की इस पीड़ा को पूरी गंभीरता से समझते हैं। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस एवं पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो सके। वर्षों तक झारखंड की चिकित्सा शिक्षा की उपेक्षा हुई, लेकिन अब महागठबंधन सरकार इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खालखो, गोल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिपिन कुमार सिंह, रांची विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ ए. एन. शाहदेव, सेंट जेवियर्स इंटरमीडिएट कॉलेज, रांची के प्राचार्य फादर अजय अनिल तिकी, रिस्स फिजियोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ शिशिर कुमार, पैनेसिया हॉस्पिटल, रांची के निदेशक डॉ. प्रशांत कुमार सहित बड़ी संख्या में नीट में सफल छात्र-छात्राएं सहित अन्य लोग मौजूद थे।

जेवीएम श्यामली में नीट के सफल विद्यार्थी सम्मानित

रांची। जवाहर विद्या मंदिर (जेवीएम), श्यामली परिसर में गुरुवार को यूनिवन बैंक ऑफ इंडिया की श्यामली शाखा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही बैंक अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन ने नीट-2026 में जेवीएम के सफल विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार और स्मृति उपहार केर सहित सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य बीएन झा ने यूनिवन बैंक ऑफ इंडिया की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

सावन

सावन मास 30 जुलाई से आरंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा

अध्यात्म और आस्था की पावन धरा पर सावन की दस्तक

नव प्रदेश संवाददाता

रांची। सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई की रात 8 बजकर 5 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 30 जुलाई की रात 9 बजकर 30 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। इस वर्ष सावन के पहले दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिससे शिव पुजा का महत्व बढ़ जाएगा। वहीं,महामृत्युंजय महादेव मंदिर, शिवपुरी कॉलोनी(हिन्ु) आज आस्था, विश्वास और

कड़ी सुरक्षा के बावजूद टूटी बैरिकेडिंग, भिड़ गये कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता



नव प्रदेश संवाददाता

रांची। रांची में नीट और जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तनातनी अब सड़क पर पहुंच गई है। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था। इसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता नीट पेपर लोक मामले को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यालय घेराव करने पहुंचे और पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला हंगामे में बदल गया। दोनों तरफ से पत्थर, टमाटर, अंडे और पानी की बोटलें फेंकी गईं। धक्का-मुक्की के बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने की भी बात सामने आई है। इस दौरान घटना की कवरेज कर रहे दो मीडियाकर्मियों के घायल होने की भी खबर है।

हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भाजपा कार्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े



इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता एक बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। इससे पहले बुधवार को भाजपा

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में निकाले गए मार्च को पुलिस ने सुभाष चौक के पास रोक दिया था। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता काफी देर तक आमने-सामने रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता 'राहुल गांधी चोर है' और 'झारखंड सरकार युवाओं को न्याय दे' जैसे

कांग्रेस में नैतिकता है तो झारखंड हुई सभी परीक्षाओं की कराए सीबीआई से जांच : आदित्य

रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर राष्ट्र को कमजोर और बदनाम करने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। कांग्रेस को राष्ट्र की कतई चिंता नहीं है। दिल्ली में अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को झकझोर के लोकतंत्र के मंदिर में धुसकर जिस प्रकार आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी की, वह निंदनीय है। सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी चाहते हैं कि देश टुकड़े टुकड़े में बंट जाए। इनकी कभी मंशा नहीं रहती कि देश अखंड रहे। साहू गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। साहू ने कहा कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। कांग्रेस लोक लाज को धोकर पी गई है। कांग्रेस के दो वेहरे हैं। यह दिल्ली में कुछ करती है और झारखंड में कुछ। झारखंड में बीते छह वर्ष में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा हो, उत्पाद सिपाही भर्ती या शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हो, जब भी परीक्षा हुआ उसका प्रश्न पत्र पहले लीक हुआ है। पिछले 06 वर्ष में कांग्रेस की मदद से लाखों युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया गया है। परीक्षा में हुई अनिमितता की जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर मौन है। जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया। दबाव के कारण जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा की मांग है कि जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हो। कांग्रेस इस पर अपना मुंह कभी नहीं खोलती।



नारे लगाते रहे तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'वोट चोर गद्दी छोड़ो', 'चंदा चोर गद्दी छोड़ो' और 'नीट पेपर लोक के आरोपी मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दो' जैसे नारे लगाए। भाजपा और कांग्रेस के

कार्यकर्ताओं के बीच हुए इस टकराव के बाद हरमू रोड पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही।

बीएयू में अत्याधुनिक प्लांट बीडिंग मॉलेक्यूलर प्रयोगशाला की स्थापना

फसल नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

नव प्रदेश संवाददाता

रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची ने अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक फसल सुधार के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्लांट ब्रीडिंग मॉलेक्यूलर प्रयोगशाला की स्थापना की है। यह नई प्रयोगशाला कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।

डीएनए निष्कर्षण, मार्कर-असिस्टेड चयन, जीनोटाइपिंग तथा मॉलेक्यूलर डायग्नोस्टिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित यह प्रयोगशाला शोधकर्ताओं तथा स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों को अधिक उपज देने वाली, बेहतर पोषण गुणवत्ता वाली तथा कीट, रोग एवं प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अधिक सहनशील फसल किस्मों के विकास में सहयोग प्रदान करेगी।

बीएयू के कुलपति डॉ एससी दुबे ने गुरुवार को इस प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ह्यूयह सुविधा हमारे संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पारंपरिक पादप प्रजनन को मॉलेक्यूलर विज्ञान के साथ जोड़कर हम नवाचार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं, जिससे किसानों,



उद्योग जगत और समाज को लाभ मिलेगा।इन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों को नई चीजें सीखने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए तथा गैर-आनुवंशिकी से जुड़े शिक्षकों को भी मॉलेक्यूलर अनुसंधान का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और वैज्ञानिक आजीवन सीखने वाले होते हैं।

प्लांट ब्रीडिंग मॉलेक्यूलर प्रयोगशाला अब पूरी तरह संचालित हो चुकी है और इसमें पीजी एवं पीएचडी छात्रों के शोध कार्य शुरू हो गए हैं। यह प्रयोगशाला क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगी तथा सरकारी एजेंसियों, कृषि अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के संपठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर जलवायु-अनुकूल फसल प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह प्रयोगशाला आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग की अध्यक्ष डॉ मणिगोपा चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में संचालित

होगी। प्रयोगशाला में मॉलेक्यूलर अनुसंधान के लिए आवश्यक सभी अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। इन उपकरणों की सहायता से रोग एवं कीट प्रतिरोध, उत्पादन सहनशीलता, अधिक सूखा सहन क्षमता, बेहतर गुणवत्ता तथा उन्नत पोषण मूल्य जैसे वांछनीय गुणों वाली फसल किस्मों के विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

लाभकारी जीनों की प्रारंभिक पहचान तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के त्वरित विश्लेषण की सुविधा मिलने से प्रजनन की अवधि और लागत दोनों में कमी आएगी तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। अंततः यह प्रयोगशाला बदलती जलवायु परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक लचीली फसल किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उद्घाटन समारोह में बीएयू के निदेशक अनुसंधान डॉ पीके सिंह तथा कृषि संकाय के अधिष्ठाता डॉ डीके शाही भी उपस्थित थे।

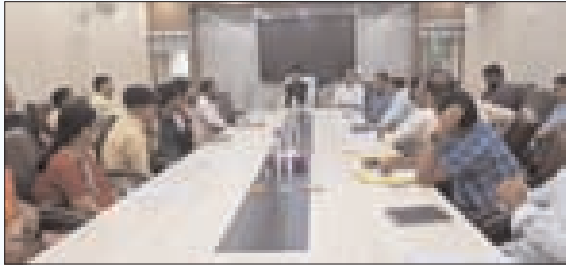
एक नजर

नीट-2026 और सीबीएसई मार्किंग विवाद पर झामुमो का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का पुतला फूँका



रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रांची जिला ने गुरुवार को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूँककर विरोध-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे, नीट-2026 एवं सीबीएसई मार्किंग में कथित गड़बड़ियों के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आयोजित किया गया। झामुमो रांची जिला संयोजक प्रमुख मुस्ताक आलम के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला एवं महानगर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा छात्र मोर्चा के सदस्यों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारी पहले जिला स्कूल परिसर में एकत्र हुए और वहां से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ति में अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। इसके बाद केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान मुस्ताक आलम ने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने के लिए की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट-2026 परीक्षा और सीबीएसई मार्किंग में कथित अनियमितताओं ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा छात्रों की मांगों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया पर विद्यार्थियों का विश्वास कमजोर होता है तो इसका सीधा असर देश के शिक्षा तंत्र पर पड़ता है। इसलिए सरकार को इस मामले में शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन में केंद्रीय सदस्य अश्विनी शर्मा, समनूर मंसूरी, डॉ. हेमलाल मेहता, धर्मेन्द्र सिंह, सोनू मुंडा, रामशरण तिकी, अफरोज अंसारी, फरीद खान सहित जिला, महानगर एवं छात्र मोर्चा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

39वें दीक्षांत समारोह की सुचारू व्यवस्था के लिए कोर कमटी की बैठक संपन्न



रांची। राज्यपाल सचिवालय, झारखंड द्वारा प्राप्त पत्र के अनुपालन में रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह के सुचारू आयोजन को लेकर आज कुलपति सम्मेलन कक्ष में कोर कमटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने की। बैठक में महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति महोदय द्वारा 39वें दीक्षांत समारोह हेतु सितंबर तक दीक्षांत समारोह पूर्ण करने के आलोक में समारोह की तैयारियों, आयोजन में मितव्ययिता एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कुलपति ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 39वें दीक्षांत समारोह के सफल एवं गरिमामय आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं। बैठक में कोर कमटी के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिनमें डीएसडब्ल्यू. प्रो. सुदेश कुमार साहू प्रॉक्टर डॉ मुकुंद मेहता, सीसीडीसी, डॉ पीके झा, कुलसचिव डॉ राजकुमार शर्मा, परीक्षा नियंत्रक संजय सिंह, वित्त पदाधिकारी डॉ दिलीप कुमार, उप निदेशक सीबीएस डॉ स्मृति सिंह, समन्वयक एनएसएस डॉ किशोर सूरिन, निदेशक कंक्ट्यू सेंटर डॉ ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह तथा, डॉ रोहित श्रीवास्तव उपस्थित थे।

बैलियम से झारखंड दौरा पर आए विद्यार्थियों ने स्पीकर से की शिष्टाचार भेंट



रांची। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत बैलियम से झारखंड दौरा पर आए विद्यार्थियों ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा का भ्रमण किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) से शिष्टाचार भेंट की और अपने झारखंड दौरे का अनुभव साझा किया। स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने विद्यार्थियों को झारखंड विधानसभा की ओर से प्रकाशित पुस्तक सदन संवाद को स्मृति-चिह्न स्वरूप भेंट की। विद्यार्थियों ने झारखंड की समृद्ध सैनजातीय संस्कृति, सामाजिक विविधता, परंपराओं और स्थानीय जीवाश्मैली को जानने-समझने के अपने अनुभवों को स्पीकर के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि झारखंड का सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य एवं यहां के लोगों का आत्मीय व्यवहार उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। वहीं स्पीकर ने बैलियम से आए विद्यार्थियों का झारखंड विधानसभा में स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमण न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि विभिन्न देशों के बीच आपसी समझ, मैत्री संबंध और ज्ञान के विस्तार को भी नये आयाम देते हैं।

झारखंड के सभी स्थानों पर 26 से 29 जुलाई तक बारिश होने की संभावना

रांची। राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी स्थानों में 26 से 29 जुलाई तक बारिश होने की प्रबल संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी। विभाग के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आने वाले दिनों में राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 27 जुलाई तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में 57.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान दुमका में 32.6 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई। हल्की बारिश होने से मौसम में ठंड महसूस की गई और सुहाना बना रहा। वहीं, गुरुवार को रांची में अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री और न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम 29.6 डिग्री और न्यूनतम 23.6 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 32 और न्यूनतम 24.6 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 30.1 डिग्री और न्यूनतम 23.2 डिग्री और चंडबासा में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।



और आपसी सद्भाव की परंपरा आज भी जीवंत है। इन्हीं मूल्यों से प्रेरणा लेकर यहां की नई पीढ़ी

शिक्षा, समाजसेवा, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में सफलता हासिल कर कॉलोनी का नाम रोशन कर रहे है।

मोहक दिखेगा मंदिर: अरविंद उपाध्याय



मंदिर के शिखर को नक्काशोंदर बनाकर एक नया और भव्य रूप दिया गया है। वहीं, संपूर्ण शिवालय में रंग-रोगन का कार्य अंतिम चरण में है। सावन माह की शुरुआत से पूर्व यह कार्य पूरी तरह संपन्न कर लिया जाएगा, जिससे मंदिर अत्यंत भव्य एवं मोहक स्वरूप में नजर आएगा। उन्होंने कहा: हमारी कोशिश है कि सावन की

शुरुआत से पहले रंग-रोगन का सारा काम पूरा कर लिया जाए, ताकि मंदिर आने वाले हर भक्त को एक अत्यंत दिव्य, शांत और सकारात्मक वातावरण की अनुभूति हो सके।

आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र
महामृत्युंजय महादेव मंदिर रांची के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सावन के महाने में यहां हत्कों का ताता लगा रहता है और भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार मंदिर का यह नया और अलौकिक स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।

सावन के सोमवार

पहला सावन सोमवार- 3 अगस्त
दूसरा सावन सोमवार- 10 अगस्त
तीसरा सावन सोमवार- 17 अगस्त
चौथा सावन सोमवार- 24 अगस्त

झामुमो ने जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में केन्द्र सरकार का किया पुतला दहन

नवप्रदेश/दुमका। दुमका स्थित सिंदो-कान्हु चौक (पोखरा चौक) में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने दुमका जिला समिति द्वारा जिला अध्यक्ष शिव कुमार बास्की के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर में छत्रोछत्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में केन्द्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छत्र-छत्राओं पर बल प्रयोग की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छत्रों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने केन्द्र



सरकार से इस घटना की जवाबदेही तय करने तथा छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। इस विरोध कार्यक्रम में ज़ामुमो

जिला सचिव निशित वरण
गोलदार, जिला प्रवक्ता अब्दुश
सलाम अंसारी, जिला संगठन
सचिव रवि यादव, जिला महिला
मोर्चा अध्यक्ष सुनीता मरांडी,
जिला सचिव सबिता टुडू, केंद्रीय

झामुमो ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का किया पुतला दहन

नवप्रदेश/गिरिडीह। जत-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान का पुतला दहन किया। पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय से पैदल मार्ग करते हुए टावर चौक पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि टएफ़-2026, सीबीएसई मार्किंग में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्यवाई लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। झामुमो ने छात्रों की मांगों पर दारुणता और लाठीचार्ज की निशमूख जांच की मांग की। सुमित कुमार, पूर्व विधायक केदार हाजरा सहित बड़ी संख्या



पर गंभीरता से विचार, शिक्षा व्यवस्था में कार्यक्रम में महापौर प्रमीला मेहर, उपमहापौर में नेता, कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे।

समिति सदस्य राजेश कुमार सिंह,
दुमका प्रखंड अध्यक्ष सिराजुद्दीन
अंसारि, प्रखंड सचिव विजय
मल्लाह, नगर अध्यक्ष विजय

दास, नगर सचिव मो. आरिफ,
उपाध्यक्ष अमित रक्षित, प्रदीप
केवट, मसलिया प्रखंड अध्यक्ष
बासुदेब टुडू, रानीश्वर प्रखंड

अध्यक्ष बाबूजान हेंब्रम सहित
झामुमो के बड़ी संख्या में सक्रिय
कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सारथी योजना को मिली मजबूती: गिरिडीह में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव, 121 युवाओं को मिले ऑफर लेटर

नवप्रदेश/गिरिडीह। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सांख्यिकी योजना के तहत गिरिडीह स्थित जे एन एस के टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में आज एक भव्य प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल दयूटी असिस्टेंट (जीएपी) और फैशन डिजाइनर (एफडी) कोर्स के 120 प्रशिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा ऑफर लेटर प्रदान किए गए। यह आयोजन राज्य के युवाओं को कौशलयुक्त बनाकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ।

गौरललब के नि:शुल्क मुख्यमंत्री सांख्यिकी योजना झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी (जेएसडीएमएस) द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण



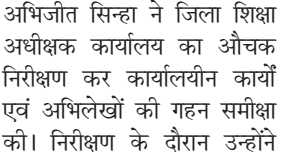
दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद
 तीन माह के भीतर रोजगार न
 मिलने पर युवाओं को 1000 रुपये
 तथा युवतियों/दिव्यांगों को 1500
 रुपये प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन
 भत्ता भी दिया जाता है।
 इस प्लेसमेंट ड्राइव का मुख्य
 उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को उद्योग
 जगत से जोड़ना था। कार्यक्रम में
 स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की प्रतिष्ठित
 संस्थाओं अलर्ट स्पेस (ज्युपिटर
 हॉस्पिटल), वीएनएस हेल्थ
 केअर, ए गृहम हेल्थ केअर ने
 जीईए एछरों का चयन किया,
 वहीं फैशन उद्योग की प्रमुख



कंपनियों ओरिएंट क्राफ्ट और कलर जर्सी ने फैशन डिजाइनर छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। सभी कंपनियों के एचआर एवं हायरिंग मैनेजर कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह के नगरपालिका अध्यक्ष श्री सुमित कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को मिल रहा यह प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर स्थानीय युवाओं के लिए वरदान साबित हो

**जनसमस्याओं के
त्वरित समाधान के लिए
विभागवार प्रतिनिधियों
की सूची जारी**

नवप्रदेश/गिरिडीह। झारखंड सरकार के मंत्री सुदित्य कुमार ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान एवं विभागीय कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए विभागावर प्रतिनिधियों की सूची जारी की है। जहाँ आदेश के अनुसार मो. सईद अख्तर को खनन विभाग, गिरिडीह का विभागीय प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। विभागीय प्रतिनिधि संबंधित विभाग से जुड़े मामलों का समन्वय करेंगे तथा आम जनता की समस्याओं के समाधान और विधायक संबंधी कार्यों के निष्पादन में सहयोग करेंगे। अपनी नियुक्ति पर मो. सईद अख्तर ने मंत्री सुदित्य कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तथा खनन विभाग से जुड़ी जनसमस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।



A group of men are gathered around a table in a library or office. One man in a dark blue shirt is looking at a book or document, while others look on. The room is filled with bookshelves and stacks of papers.



**पितों की अनसुनी
जा अब तक नहीं**

कंपनियों से भी इसका शुल्क वसूलता है। लेकिन इस डैम प्रभावित 116 गांव और 84 मौजा के लोग आज भी फ्रंट में बंद हैं। जिला स्तर पर होने वाली आबादी की बैठक में भी सिर्फ पानी का स्तर 180.22 मीटर से नीचे रखने की सलाह दी जाती है। विस्थापितों का कहना है कि विस्थापन नीति के तहत उन्हें अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। आशिक जमीनों में भी डैम के जलाशय में डूब गई हैं।

राज्य सरकार पानी बेचकर रेवेन्यू तो ले रही है, लेकिन उसी राशि से विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। स्थानीय लोगों का सवाल है कि चाँडिल जलाशय से मिलने वाले

ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभार्थी जिले के प्रत्येक पात्र छात्र-छात्रा तक समय पर पहुंचे, वह शक्ति विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

अनसुनी क नहीं

रेवेन्यू का पैसा आखिर कहां खर्च हो रहा है। आज तक न तो डैम की समुचित देखरेख और मटेनेंस के लिए कोई ठोस योजना बनी, न ही परियोजना के वादे पूरे हुए। परियोजना के तहत 8 मेगावाट बिजली उत्पादन और कृषि भूमि को पानी की आपूर्ति का लक्ष्य था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। विस्थापितों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और सांसद ने अब तक कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया। अगर उठाया जाता तो 44 साल से चली आ रही उनकी पीड़ा काफी हद तक कम हो सकती थी। अगर सवाल यही है कि चुनाव के समय आने वाले विस्थापितों की सुध सरकार कब लेगी?

एक नजर

नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने फूँका पीएम व शिक्षा मंत्री का पुतला

नए प्रदर्श/सरायकेला। नीत पेंपर लीक मामले तथा नई दिल्ली में छात्रों और विपक्षी नेताओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार शाम आकाशवाणी लोक पर प्रथममंत्री जयदेव मोदी और केद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रथान का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राज बागुची ने किया। कांग्रेस नेताओं ने आशंका लगाया कि नीत परीक्षा में हुई अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। साथ ही दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला माना जाता। कांग्रेस ने केद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, शिक्षा अनियमितताओं पर संसद में चर्चा तथा प्रदर्शनकारियों पर रजम मामलों को वापस लेने की वही पूर्ण विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कार्यक्रम को नैतिक समर्थन दिया। कार्यक्रम में देवु चटर्जी, राणा सिंह, प्रिस सिंह, सुरेश धारी, उमदे शर्मा, जगदीश नारायण चौबे, राणा सिंह, वैद्य संजय कुमार, रिजवान खान, संतोष सिंह, अनिल ठाकुर, खिरोडे सरदार, कमल अखतर, अजय सिंह, समरदेव नाथ तिवारी, राहुल यादव, रमेश बालानाथन, रुद्रदेव चाकी, केपी तिवारी, फूलकांत झा, उर्मिला, पूर्वी देवी, अमजुद शर्मा, प्रिस सिंह, उपेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वाहन चोरी के नेटवर्क पर आरआईटी पुलिस का बड़ा प्रहार, तीन शातिर गिरफ्तार

न्यायप्रदेश/सरायकेला। सरायकेला-खरसावां जिले के आरआईडी थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है, आरआईडी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की तीन मोटरसाइकिलों के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने नारामम वाहनों को विधिवत जांच कर लिया है तथा गिरफ्तार किए गए आरोपितों को न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार कुलूपगंगा फुटबॉल मैदान के सहिष्णु सड़िये गतिविधियों की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रविवंत प्रभुशर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, अभियान के दौरान तीन युवकों को चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ पकड़ा गया, पछुताए आर जांच के बाद वाहन को से जुड़े मामले में उनके विरुद्ध विधियुग्मन्त कार्रवाई की गई।

ईचागढ़ में हाथियों का आतंक, खेत-
खलिहान से घर तक दहशत

प्रायदेशी ईवांगल।
विद्यानसभा क्षेत्र में
इन दिनों हाथियों का
आतंक बढ़ गया है।
खेत से लेकर
खलिहान तक किसान
परेशान हैं और आम
जनता भयभीत होकर
घरी रही है। शाम ढलते
ही राहगीरों में भी डर
का माहौल है। आप दिन हाथी-मानव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि ईवांगल थाना क्षेत्र के सालकुडीह के आसपास
दो जंगली हाथियों ने किसानों की खड़ी फसल को तहस-नहस कर दिया।
ग्रामीणों के अनुसार शाम ढलते ही हाथियों का झुंड जंगल छोड़कर
सुदूरवासी गांवों में घुस जाता है और घरों को निशाना बनाकर रखे अनाज
को अपना निवाला बनाता है। बरसात के समय मिट्टी के घरों को सबसे
अधिक नुकसान पहुंच रहा है। कई बार दीवार टूटने से सोए हुए परिवार के
लोग घायल भी चुके हैं। इससे पूरे क्षेत्र का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो
गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चाँदिल वन क्षेत्र के पदाधिकारी सिर्फ
टॉटों, मोबिल और पटाखे लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।
हाथियों को भगाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। मजबूरन लोग
ईश्वर भरोसे भजन बिता रहे हैं।

समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण

नगरपदेश/इचागढ़। झाखरुई शिक्षा परियोजना, सारायकेला-खरसावां के तलाववायान में समारोही शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के आद्योग छात्र-छात्राओं के लिए सहायक सामग्री वितरण शिविर का आयोजन प्रखंड संसाधन केंद्र कुकशू में किया गया। शिविर में दिव्यांग बच्चों को उनकी आभश्यकता के अनुसार खिलचयन, ट्राइसाइकिल, बैकपासी, वॉकर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट रैक, ब्रेल किट सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इन उपकरणों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही। कार्यक्रम में जिला स्तरीय एपीओ सुचरित तिवारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार विभागधिकाारी संजय कुमार जोशी, एलीमों की टीम से राम कुमार सिंह, सोमोनी कुमार, महेंद्र कुमार एवं लाल कुश कुमार, सिचार् चिंत तथा शिक्षक प्रतिलोचना कुमार और गुणाधर महतो उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों के अभिभावक भी शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे आत्मनिर्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर अभिभावकों ने झाखरुई शिक्षा परियोजना एवं शिक्षा विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

**लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने चार्टर
नाइट कार्यक्रम किया आयोजित**

नवप्रदेश/गिरिदिह। लायंस क्लब ऑफ गिरिदिह एलीट ने अपने 7 वें स्थापना दिवस के अवसर पर लायन सतेन्द्र सिंह के आवास पर चाढ़ा नाइट कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष लायन राहुल बर्मन तथा संचालन लायन राहुल कृष्णा ने किया। इस कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन लायन धर्म प्रकाश मुखर्ज्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लायन राहुल बर्मन ने कहा कि हमारा क्लब इस वर्ष वर्षारोपन, मेमोराबल हेल्थ चेकअप और ट्रैपिक अर्नेस को प्राथमिकता देगा। इस वर्ष खंडेली लायनशेड के चारों ओर 1000 से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लायन राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिदिह एलीट हमेशा से सामाजिक कार्यों तथा मानव सेवा के अग्रगण्य में अपनी महती भूमिका निभाई है। क्लब के तमाम सदस्यों से आग्रह किया गया कि अपनी व्यस्त मानवजीवन से समय निकाल कर सेवा कार्यों में अपना योगदान दें। मुख्य अतिथि लायन धर्म प्रकाश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिदिह एलीट रीजन 8 का एक अहम और मजबूत क्लब हैं जो अपने दायित्व को शत प्रतिशत निभानेवा है। इस वर्ष क्लब रीजन 8 की नई बल्कि डिस्ट्रिक्ट 322अ में महत्वपूर्ण स्थान पर रहेगा। सिचिव लायन डॉ सुनम कुमार ने कहा कि 26 जुलाई को रीजन 8 के 13 क्लब पदाध्यक्षियों का स्कूलिंग तथा क्लब का पदस्थापना समारोह सेलिब्रेशन सिरिसिया गिरिदिह में आयोजित किया जाएगा। पदस्थापना समारोह का उद्घाटन माननीय अमीजी श्री सुदित्य कुमार सानू करेंगे। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट 322अ के कई पदाधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कोषाध्यक्ष लायन मसरूस आलम सिद्दीकी ने तमाम सदस्यों से आग्रह किया कि 26 जुलाई के कार्यक्रम में सभी सदस्य अपनी अपनी सहभागिता दें। इस कार्यक्रम का मेजबानी लायन सतेन्द्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में लायन दशरथ प्रसाद लायन सुनील कुमार लायन लायन उदय भदानी लायन डॉ ज्ञान प्रकाश लायन डॉ दीपक कुमार लायन अरुण कुमार साव लायन राहुल कुमार लायन गौतम सागर लायन मुकुेश आनंद लायन शशुज सिंह लायन रंजीत कुमार सिन्हा लायन दिव्यजीत सिंह लायन गुंजन कुमार शर्मा लायन लक्ष्मीकांत साव सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

नवप्रदेश/चाडिल। सरायकेला-खरसावा जिले की चाडिल सुवर्णखाबा बहुउद्देशीय परियोजना की वन 44 साल से ज्यादा हो गए। हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है, लेकिन विस्थापितों की पीड़ा आज भी वही है। एक तरफ सरकार डैम से हर साल करोड़ों का रेवेन्यू-मुआवजे का सौदा कर रही है, दूसरी तरफ 116 गांवों के विस्थापित अब तक मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। चाडिल डैम से सरकार को अब तक कुल 717 करोड़ 67 लाख रुपये का रेवेन्यू मिला है। अबकले 2025-26 में 127 करोड़ और अप्रैल 2026 में ही 65 करोड़ 28 लाख रुपये जमा होंगे। इसमें 583 करोड़ 54 लाख रुपये का डैम कंपनी ने बकाए के तौर



पर दिए हैं। जल संसाधन विभाग अन्य कंपनियों से भी शुल्क वसूलता है। लेकिन इस डैम से प्रभावित 116 गांव और 84 मौजा आज भी आरएल में बंद हैं। जिला प्रशासन की आबदा बैठक में सिर्फ पानी का स्तर 180.22 मीटर से नीचे रखने की बात होती है। विस्थापितों का आरोप है कि उन्हें विस्थापन नीति के तहत पूरा

मुआवजा नहीं मिला। आंशिक जमीनें भी डूब गईं। 8 मेगावाट बिजली और कृषि को पानी देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। सवाल ये है कि करोड़ों के रेवेन्यू से विस्थापितों की समस्या क्यों नहीं सुलझी? विस्थापितों का कहना है कि सरकार आरएल के नाम पर विस्थापन को टाल रही है। 44 साल बाद भी चाँडिल डैम के



सदन से सड़क तक शिक्षा पर संग्राम

देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट परीक्षा एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पेपर लोक के आरोपों ने न केवल लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई है, बल्कि इस मुद्दे ने संसद से लेकर सड़क तक तीखा राजनीतिक संघर्ष भी खड़ा कर दिया है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मद प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा करते हुए विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक टकराव गहराता जा रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक निष्पक्ष चर्चा संभव नहीं है। विपक्ष इसे नैतिक जवाबदेही का प्रश्न बता रहा है। संसद परिसर में प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर धरना और देशव्यापी आंदोलन की घोषणा इस बात का संकेत हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को जनआंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी में है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष पहले से शर्तें लगाकर सार्थक बहस से बच रहा है और छात्रों के हितों की बजाय राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। इस विवाद के बीच व्यापम कार्रवाई का उल्लेख भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2015 के व्यापम प्रकरण और वर्तमान नीट विवाद के बीच समानताएं बताते हुए सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियाँ और जार्ज अलग-अलग हैं, इसलिए देश की प्रत्यक्ष तुलना का अंतिम निष्कर्ष संबोधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर ही निर्भर करेगा। फिर भी विपक्ष इस तुलना के माध्यम से सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस पूरे विवाद में सबसे अधिक प्रभावित कौन है। इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है—देश के लाखों छात्र। वर्षों के कठिन मेहनत, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की उम्मीदें ऐसी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर निर्भर करती हैं। यदि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर जनता का भरोसा कमजोर होता है। इसलिए यह मामला किसी एक मंत्री, दल या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था की साख से जुड़ा है। लोकतंत्र में संसद जवाबदेही तय करने का सर्वोच्च मंच है। यदि विपक्ष के पास गंभीर आरोप हैं तो उन्हें तथ्यों के साथ सदन में रखना चाहिए। वहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जांच की स्थिति, सुधारात्मक कदमों और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी देश के सामने रखे। इस्तीफे की मांग राजनीतिक परंपरा का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो तथा दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कठोर दंड मिले। आखिरकार, शिक्षा राजनीति का सबसे आसान हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। संसद का गतिरोध और सड़क का आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर छात्रों का भविष्य है। सरकार और विपक्ष दोनों को राजनीतिक टकराव से आगे बढ़कर परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर सहमति बनानी चाहिए। यही लोकतंत्र की परिपक्वता और विद्यार्थियों के प्रति वास्तविक उत्तरदायित्व का परिचायक होगा।

मुद्दा

लीक पर चयनित सोच

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ उनके सपनों, वर्षों की मेहनत और परिवार की उम्मीदों का आधार होती हैं। जब किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है, तब लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास टूटता है। यही कारण है कि पेपर लीक का मुद्दा आज राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि इस गंभीर विषय पर भी राजनीतिक दल अक्सर सिद्धांत से अधिक सुविधा का सहारा लेते दिखाई देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष लगातार कई सरकार पर पेपर लीक की लेकर हमलावर हैं। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार जवाबदेही से बच रही है। विपक्ष का यह अधिकार भी है कि वह सरकार से कठोर प्रश्न पूछे। किंतु लोकतंत्र में यही कसौटी विपक्ष पर भी समान रूप से लागू होती है। यदि पेपर लीक राष्ट्रीय शर्म का विषय है, तो क्या यह प्रश्न सिर्फ केंद्र सरकार से पूछा जाएगा या उन राज्यों से भी, जहाँ कांग्रेस अथवा उसके सहयोगी दलों की सरकारों के दौरान ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं? इसी संदर्भ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के बयान को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीपूष गौतल ने कांग्रेस के चयनात्मक रवैये पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने झारखंड में हिंदी और विज्ञान परीक्षा, तेलंगाना में इंटरमीडिएट भाषा परीक्षा, एसएससी भाषा परीक्षा, तमिलनाडु में बी.एड. परीक्षा, पश्चिम बंगाल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पंजाब में गृह-डी भर्ती, केरल की लोक सेवा आयोग परीक्षाओं तथा कर्नाटक की परीक्षा से जुड़े मामलों का उल्लेख किया है। वे बताते हैं कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा अनियमितताओं की लंबी सूची रही है। उनका प्रश्न था कि यदि हर पेपर लीक शर्मनाक है, तब फिर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी समान क्यों नहीं है? वरन्तु, उपलब्ध सार्वजनिक विवरण यह संकेत देते हैं कि पेपर लीक की समस्या किसी एक दल, एक सरकार या एक दशक तक सीमित नहीं रही। वर्ष 2004 से 2014 के बीच केंद्र तथा विभिन्न राज्यों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक अथवा गंभीर परीक्षा अनियमितताओं के मामले सामने आए। उपलब्ध सूची के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर गुपीएससी, एसएससी, एनडीए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आरबीआई, आईबीपीएस, कैट, गैट, वलेंट, रेलवे भर्ती, डीआरडीओ और अन्य प्रतिष्ठित परीक्षाएँ भी विवादों से अछूती नहीं रही। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, असम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अन्य राज्यों में भी निश्चित भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद सम्व-समय पर सामने आए हैं। इसके बाद भी स्थिति पूरी तरह नहीं बदली। सरकार नय नियम बनाती है और अपराधी उम्मेदों से निकलने का रास्ता तैयार करके रखता है। अपलब्ध विवरण के अनुसार 2006 से 2024 के बीच एसएस, आउटर्सईड, रेलवे भर्ती, टीएनपीएससी, मुंबई विश्वविद्यालय, जम्मू-कश्मीर मेडिकल प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान रीट, झारखंड सीजीलएल, बिहार भर्ती, राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती तथा अन्य कई परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए। इन मामलों के दौरान अलग-अलग समय में कांग्रेस, भाजपा और अनेक क्षेत्रीय दलों की सरकारें सत्ता में थी। वह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि समस्या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रही, यह पूरे परीक्षा तंत्र में गहराई तक फैली हुई है। यही से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि कांग्रेस आज केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है, तो क्या वह अपने शासनकाल या अपने सहयोगी दलों की सरकारों के दौरान सामने आए मामलों पर भी उतनी ही स्पष्टता से आत्ममंथन करेगी? क्या वह यह स्वीकार करेगी कि परीक्षा प्रणाली की कमीयों ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया? क्या वह उन राज्यों में भी समान राजनीतिक और नैतिक मानदंड लागू करने की मांग करेगी, जहाँ उसके नेतृत्व या समर्थन वाली सरकारों के दौरान ऐसी घटनाएँ हुई?



सत्यजीत दाता

एक पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने से जो आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है, वह तभी तक नहीं बंधता जब तक कि सही तकनीक में किए गए निवेश से कहीं अधिक होता है। दोबारा परीक्षा कराने की प्रशासनिक लागत, विद्यार्थियों के समय की बर्बादी और सबसे बढ़कर व्यवस्था पर उठने वाला सवाल, ये सभी मिलकर यह साबित करते हैं कि सही तकनीक में शुरूआती निवेश आगे चलकर कहीं अधिक बचत लाता है।



प्रमोद भार्गव

विदेशी धनवान जब किराए की कोख से संतान पाने के इच्छुक होते हैं तो वे भारत आकर एक साथ कई महिलाओं को गर्भधारण करा देते हैं। इनमें से कुछ महिलाओं में यह प्रयोग सफल हो जाता है तो वह किसी एक महिला को छोड़ बाकी का गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात कराई गई महिलाओं को कोई धन भी नहीं दिया जाता था। यह सरासर अन्याय व अनैतिकता थी। इसी अध्ययन से खुलासा हुआ था कि कोख की कीमत कई हजार डॉलर है लेकिन इस राशि में सा सरोगेसी मां को महज 1 या 2 प्रतिशत धनराशि ही बांमुश्किल मिल पाती है।



डॉ. अरविंद नाथ तिवारी

बिहार में उर्वरक वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाना होगा। प्रत्येक जिला में मांग के अनुरूप अग्रिम भंडारण, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, नियमित निरीक्षण तथा दोषी विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

केंद्र सरकार किराए की कोख यानी सरोगेसी मदर की क्लोनिक के नाम पर खुली मनमानी दुकानों पर अंकुश लगाने जा रही है। अब कुकुरमुत्तों की तरह देशभर में खुल रही नई दुकानें खोलने पर सख्ती बरती जाएगी। सरोगेसी केंद्रों और इनमें होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने इसमें पंजीयन और संचालन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत इन केंद्रों की अब उपग्रहों द्वारा निर्यंत्रित किया जाएगा। अब केवल राष्ट्रीय पोर्टल और ऑनलाइन आवेदन ही होंगे। इस पर निगरानी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से होगी। कामजी आवेदन व दस्तावेजीकरण की सुविधा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। ये क्लोनिक अन्य दूसरे क्लोनिक को चिकित्सा सुविधा नहीं दे सकेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

दरअसल, किराए की कोख का व्यवसायीकरण हो रहा है। यह इस तथ्य से पता चला कि कुछ ही सालों के भीतर देश में 35 से 50 प्रतिशत केंद्रों की संख्या बढ़ गई। इसी अनुपात में देश-विदेश में ठगी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हैदराबाद में ऐसा प्रसिद्द पकड़ा गया, जो 2 से 4 लाख में कोख किराए पर लेकर 30 लाख रुपए तक में बेच देते थे। यहां तक कि विदेशों से भी शुक्राणु दानदाता लाए गए। यानी देश के बाहर भी बच्चे बेचे गए। हालांकि 2025 में सरकार ने शुक्राणु दाता नियमों में बदलाव किया था, लेकिन कारोबारियों ने इन नियमों की अनदेखी की। नाबालिग और अविवाहित लड़कियों की कोख का भी अवैध इस्तेमाल किया गया। भारत में कोख किराए से लेने का खर्च 10 से 25 लाख है, जबकि विदेशों में 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपए तक है। इसलिए सरोगेसी क्लोनिकों में किराए की कोख अवैध कारोबार का बड़ा धंधा बनती जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु में सरोगेसी के अनेक उद्योग के मामले सामने आए हैं। इसलिए सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। इसके पहले 2025 में लिंव इन और सम्लैंगिक युगलों को किराए की कोख के जरिए माता-पिता बनने का अधिकार देने से साफ मना कर दिया था। अब ऑनलाइन जानकारी होने से निगरानी तंत्र के पास सरोगेसी क्लोनिक संचालन व नवीनीकरण संबंधी जानकारी हर वक्त सामने होगी। इससे अनियंत्रित कोशों का आसानी से चिन्हित कर लिया जाएगा। क्लोनिक के पास



क्या वैध दस्तावेज हैं, इसकी भी पुख्ता जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी कमी पाए जाने पर संस्था को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इन केंद्रों के कर्मचारियों और बच्चों के जन्म की जानकारी भी मिलती रहेगी। सरकार इन नियमों को एक साथ लागू करने की बजाय चरणबद्ध अमल में लाएगी। वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के प्रयोग की अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा पारिीरक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। अर्थात इन हालात में वैवाहिक जोड़ा सरोगेसी मदर का साहारा ले सकता है। कानून के अनुसार यह भी बाध्यकारी शर्त है कि किराए की कोख देने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए और कम-से-कम उसका एक बच्चा भी हो। साथ ही पति की आयु 26 से 55 वर्ष और पत्नी की आयु 23 से पचास वर्ष के बीच होना आवश्यक है। किराए की कोख के कानून में परिवर्तन इसके बढ़ते अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से किया गया है। अब केवल नि:संतान दंपति जो बच्चे पैदा करने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। इस सुविधा को कानूनी भाषा में अल्ट्रस्टिक सर्जरी सरोगेसी कहा जाता है। भारत दुनिया के दंपतियों के लिए किराए की कोख का बड़ा व्यावसायिक नाभिकेंद्र बनता जा रहा है, जो सुविधा वास्तविक जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी, वह अमीर दंपतियों के लिए शौक में तब्दील होती जा रही है। सूचना तकनीक के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें किराए पर कोख दिए जाने का धंधा भी शामिल है। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक

भारत प्रसूति पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं।

भारत में किराए की कोख का कारोबार अरबों डॉलर का हो गया है लेकिन यह धंधा अंततः प्रकृति की प्रतिरूप महिला की कोख पर टिका है, ठीक उसी तरह जिस तरह, उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रकृति के गर्भ में समाई खनिज संपदाओं के दोहन पर टिकी है। इस धंधे की भारी कीमत उन महिलाओं को चुकानी पड़ी है, जिन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए हर हाल में धन की जरूरत रहती है। अतएव 2016 में प्रजनन सहायक तकनीक विधेयक लाकर केंद्र सरकार ने इस गोरखधंधे पर अंकुश लगाने की पहल कर दी थी। जो एक सही कदम रहा है। लेकिन इस कानून से उन्हें परेशानी है, जिन्होंने स्त्री की आर्थिक कमजोरी को वस्तु में डालकर उसकी कोख को बाजार के हवाले कर दिया है। वे यह भी दलील दे रहे हैं कि कठोर कानून से विदेशी मुद्रा का आगमन रुक जाएगा।

सरोगेसी मां बनने के लिए महिला को इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके लिय जैविक माता-पिता के शुक्राणु और अण्डाणु को परखनली में प्रत्यारोपित किया जाता है। गभाधान का यही एकमात्र उपाय है। इसका शरीर पर विपरीत असर पड़ता है, इसके गर्भपात होने की 80 फीसदी आशंका रहती है। ऐसी 90 प्रतिशत प्रसूति शल्यक्रिया के जरिए होती हैं। ऐसे में महिला की जान का संकट भी बना रहता है। इस स्थिति में कोख किराए से देने वाली महिला का न तो कोई बीमा होता था, न ही उससे पति और बच्चों की कोई गारंटी लेता था। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी बड़ा सवाल था

कि जैविक अविभावक यदि जन्म के बाद बच्चे को छोड़कर नौ-दो-न्यारह हो जाते हैं तो उसके पालन-पोषण की जवाबदेही किसकी थी? यदि नवजात शिशु विकलांग या ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ पैदा होता है और जैविक माता-पिता उसे लेने से इनकार कर देते हैं तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेता? ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो किशतों पर कोख किराए पर देती थीं। ऐसी ही सुविधाओं के चलते भारत में किराए की कोख वैश्विक राजधानी बन गया था।

इस बाबत एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन ने चौंकाने वाले सवाल भी उठाए थे। खासतौर से विदेशी धनवान जब किराए की कोख से संतान पाने के इच्छुक होते हैं तो वे भारत आकर एक साथ कई महिलाओं को गर्भधारण करा देते हैं। इनमें से कुछ महिलाओं में यह प्रयोग सफल हो जाता है तो वह किसी एक महिला को छोड़ बाकी का गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात कराई गई महिलाओं को कोई धन भी नहीं दिया जाता था। यह सरासर अन्याय व अनैतिकता थी। इसी अध्ययन से खुलासा हुआ था कि कोख की कीमत कई हजार डॉलर है लेकिन इस राशि में से सरोगेसी मां को महज 1 या 2 प्रतिशत धनराशि ही बांमुश्किल मिल पाती है। बाकी अस्पताल के चिकित्सक और बिचौलिये हजम कर जाते थे।

अप्रवासी भारतीयों में सरोगेसी का मुद्दा बहुत ज्यादा थी। यदि स्त्री स्वस्थ व सुंदर होने के साथ उच्च जाति और उत्तम पारिवारिक पृष्ठभूमि से होती थी तो उसे ज्यादा पैसा दिया जाता था। अप्रवासी दंपति भारत आकर किराए की कोख द्वारा बच्चा पैदा करना इसलिए भी अक्षम मानते थे, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने को भारत से जुड़ा पाते थे, नतीजतन भारत में सरोगेसी की मांग तेजी से बढ़ रही थी। वर्तमान में अमीर घरों की स्त्रियां शौक के लिए या बच्चा पैदा करने के कठिन दायित्व से बचने के लिए किराए की कोख से संतान पैदा कर रही हैं। अतएव यह कारोबार निरंतर बढ़ रहा था। यहां तक कि नाबालिग और अविवाहित लड़कियां भी इस धंधे में धन कमाने के लिए उत्तरती चली आ रही थीं। इसलिए इस कानून में नए बदलाव जरूरी थे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

बिहार में यूरिया की स्थिति: चुनौती, कारण व समाधान



वितंब होता है, जिससे कृत्रिम संकट की स्थिति बन जाती है। उर्वरक संकट का एक अन्य कारण असंतुलित उपयोग भी है। अनेक किसान वैज्ञानिक सलाह के बजाय केवल यूरिया पर अधिक निर्भर रहते हैं। इससे यूरिया की मांग अवाचन बढ़ जाती है, जबकि फसल को संतुलित पोषण नहीं मिल पाता। कृषि वैज्ञानिक लगातार सलाह देते रहे हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग ही अधिक उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय है। केवल यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता भी घट सकती है। केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाती रही हैं। उर्वरक की आपूर्ति की नियमित निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद जूनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद जूनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद जूनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद जूनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद जूनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद जूनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

लाइसेंसधारी विक्रेताओं का निरीक्षण जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कई जिलों में कृषि एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद-बीज दुकानों की जांच भी की जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में वाल्मीकिनगर के सांसद जूनील कुमार ने नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की संयुक्त सचिव वदना प्रेयसी तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक (मूवमेंट) अभय कुमार से मुलाकात कर बिहार, विशेष रूप से वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है इसलिए निगरानी, जिला स्तर पर भंडारण की समीक्षा, कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तथा

एआई, व डिजिटल निगरानी से मजबूत हो सकती है परीक्षा प्रणाली

हाहत की बात होगी, वहीं यह उन ईमानदार उम्मीदवारों के लिए न्याय का भी कार्य है जो वर्षों की पढ़ाई के बाद परीक्षा देने आते हैं। एआई तकनीक से संचालित सीसीटीवी निगरानी एक कदम और आगे जाती है। पारंपरिक सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल ज्यादातर फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था, जिसका विश्लेषण घटना घटित होने के बाद किया जा सकता था। एआई से युक्त सीसीटीवी कैमरे उम्मीदवार के असामान्य व्यवहार, जैसे लगातार इश्ट-उधर देखना, अनधिकृत सामग्री का कब्जा और परीक्षा हॉल में बाहरों व्यक्तिों के प्रवेश का पता लगा सकते हैं। एक केंद्रीय रूप से नियंत्रित कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ जगो ब्यांडेड स्पॉट निगरानी प्रणाली सैकड़ों परीक्षा केंद्रों की एक साथ, बिना किसी चूक के निगरानी करने की अनुमति देगी। यह केवल परीक्षा हॉल तक ही सीमित नहीं है; प्रश्न पत्रों की छपाई, पैकिंग और परिवहन जैसी अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जिनके लिए समान सावधानी की आवश्यकता होती है। सुरक्षित प्रिंटिंग जोन, डिजिटल निगरानी और नियंत्रित पहुंच का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने तक अपनी पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षित हैं। पेपर लीक परीक्षा हॉल के बाहर, आपूर्ति श्रृंखला की ऐसी ही किसी कमजोर कड़ी में होते हैं, इसलिए तकनीक आधारित निगरानी का उपयोग पूरी प्रक्रिया में किया जाना चाहिए। अब आंकड़ों में भी इस बात का प्रमाण है कि तकनीक आधारित परीक्षाएं काम करती हैं। आधुनिक तकनीक से युक्त मानकीकृत रूप के



परीक्षा केंद्र कम समय में लाखों उम्मीदवारों की सफल परीक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कई राज्यों ने सरकारी परीक्षाओं के लिए इन्हें एक पसंदीदा मानक के रूप में सुझाया है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक अकेले इसका जवाब नहीं है। एआई और निगरानी का उपयोग तभी लाभदायक है जब इसके साथ स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रियाएं मौजूद हों, आवश्यक विवरणों के साथ ईई संभालने वाले कर्मचारी हों और साथ ही लोगों को जवाबदेह बनाने वाला ढांचा हो। यह तकनीकी उपकरण है जो अनियमितताओं का पता लगा सकता है लेकिन संस्था की क्षमता यह तय करती है कि इस चेतावनी पर कितनी तेजी से ध्यान दिया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। भारत जैसे देश के आकार को देखते हुए, जहाँ एक ही परीक्षा के लिए करोड़ों विद्यार्थी पंजीकरण कराते हैं, इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन एआई, बायोमेट्रिक

निगरानी और डिजिटल निगरानी के रूप में तकनीक के उचित क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि सभी विद्यार्थियों को एक समान, सुरक्षित और निष्पक्ष अवसर मिले। भारत की तुलना में दुनिया के कई अन्य देशों में परीक्षा प्रणाली अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर काम करती है इसलिए उनके मॉडल को जस का तस भारत में लागू करना संभव नहीं होता है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों भी बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल निगरानी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन वहां परीक्षा केंद्रों की संख्या और उम्मीदवारों का ध्यान में रखते हुए ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जो छोटे शहरों और कस्बों के परीक्षा केंद्रों में भी उतनी ही प्रभावी ढंग से काम करे जितना बड़े महानगरों में करता है। यही कारण है कि तकनीक को स्थानीय

जरूरतों के अनुसार ढालना उतना ही जरूरी है जितना उसे अपनाना। इस पूरी प्रक्रिया में निवेश और लागत का सवाल भी स्वाभाविक रूप से उठता है। किसी को यह लग सकता है कि एआई आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी तकनीकें महंगी होंगी, लेकिन इसे एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना जरूरी है। एक पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने से जो आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है, वह तकनीक में किए गए निवेश से कहीं अधिक होता है। दोबारा परीक्षा कराने की प्रशासनिक लागत, विद्यार्थियों के समय की बर्बादी और सबसे बढ़कर व्यवस्था पर उठने वाला सवाल, ये सभी मिलकर यह साबित करते हैं कि सही तकनीक में शुरूआती निवेश आगे चलकर कहीं अधिक बचत लाता है। इस पूरी बहस में एक पहलू जो अक्सर पीछे छूट जाता है, वह है विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति पर इसका असर। जब कोई विद्यार्थी वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है, तो उसके मन में पहले से ही पर्याप्त तनाव होता है। ऐसे में अगर उसे यह भी आशंका हो कि पेपर लीक हो सकता है, तो परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हो सकती है या कोई अनुचित तरीके से लाभ उठा सकता है, न कि तनाव कई गुना बढ़ जाता है। एक सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित परीक्षा केंद्र न केवल गड़बड़ियों को रोकता है बल्कि विद्यार्थी को यह भरोसा भी देता है कि

उसकी मेहनत का सही मूल्यांकन होगा। यह मानसिक शांति, परीक्षा के दिन के प्रदर्शन पर भी सकारात्मक असर डाल सकती है। आगे की राह देखें तो एआई और बायोमेट्रिक तकनीक का दायरा केवल पहचान सत्यापन और निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से यह पहले से ही पता लगाया जा सकेगा कि किन परीक्षा केंद्रों में जोखिम अधिक है, ताकि वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा सके। रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, केंद्रीकृत डैशबोर्ड और स्वचालित रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं परीक्षा संचालन संस्थाओं को तेज और सटीक फैसले लेने में मदद करेंगी। इसके साथ ही, सरकार, शिक्षा बोर्ड और तकनीक प्रदाता कंपनियों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि नीति और तकनीक दोनों साथ मिलकर काम करें। अंततः, परीक्षा प्रणाली में सुधार केवल तकनीक अपनाकर भर से नहीं होगा। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण चाहिए, जिसमें तकनीक, प्रक्रिया, प्रशिक्षित कर्मचारी और जवाबदेही की संस्कृति, सभी शामिल हों। जब वह सभी तत्व मिलकर काम करते हैं, तभी परीक्षा हॉल विद्यार्थियों के लिए ऐसी जगह बन पाता है जहां उनकी मेहनत और काबिलियत ही एकमात्र मानदंड होते हैं, न कि व्यवस्था की खामियां। भारत जैसे विशाल और विविध देश में यह भरोसा कायम रखना ही वास्तव में शिक्षा और अवसर की समानता की नींव है।

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद को मिला वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम का पेटेंट

एग्रीकल्चर साइंस सेंटर बलियापुर में हुआ सफल ट्रांसफर, जल संरक्षण में मिलेगा लाभ

चोरसिया, विरमानी हर्षवर्धन
सोलंकर, ओम कुमार
सनल रॉय, सचिन कुमार
शुभम कुमार कुरें और डॉ.
बिन्दु प्रियदर्शिनी सह-
इन्वेटर रहे। पेटेंट के लिए
आवेदन वर्ष 2022 में किया
गया था। संस्थान के
अनुसार इस तकनीक का
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी
पूरा हो चुका है। शोध के
तहत विरसित डिवाइस को
कृषि विज्ञान
केन्द्र, बलियापुर में स्थापित
किया गया है। वहां इसका
उपयोग जल आपूर्ति के
बेहतर प्रबंधन के लिए

किया जा रहा है।

डॉ. राजीव कुमार रजन ने कहा, हमारा उद्देश्य ऐसी किफायती और उपयोगी तकनीक बनाना था जिससे जल का बेहतर प्रबंधन हो सके। यह खुशी की बात है कि यह तकनीक लैब से निकलकर सीधे किसानों तक पहुंची। हमें उम्मीद है कि भविष्य में इसका उपयोग और अधिक क्षेत्रों में होगा।

आईईईई यूएसए ने किया सहयोग.....

जानकारी के अनुसार यह शोध

काय लगभग सात लाख रुपये की प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ। इस प्रोजेक्ट को ईस्टीटाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनियर्स इंजीनियर्स की ग्रुपएस इकाई आईई ग्रुपएस से फाइनंशियल सहयोग मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम एप्रोक्रियल, स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थानों में जल वितरण और संरक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। इस उपलब्धि को समाज की जरूरतों में अनुरूप उपयोगी तकनीक विकसित कर उसे जमीन तक पहुंचाने की दिशा में आईआईटी (आईएसएफ) धनबाद का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कनकनी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ने अस्पताल कर्मचारी द्वारा डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज किए जाने का गंभीर मामला सामने आया

प्रभाकर (लोहा)बाद - कान्कनी शहरी
 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल
 कर्मचारी द्वारा डॉक्टर बनकर मरीजों
 का इलाज किए जाने का गंभीर मामला
 सामने आया है। जुनावा को एक मरीज
 ने विस्तृत के समक्ष ऑन-रिकॉर्ड
 के लकड़का गाने निवासी शंकर
 खुलुतासा किया, जिसके बाद स्वास्थ्य
 केंद्र की कार्यपालनी पर सराव उठने
 लगे है। जन्मरक के अनुसार, कान्कनी
 के लकड़का गाने निवासी शंकर
 प्रभाकर, जो 12 दिन अग्रे असुराल
 भाजपाजो 12 इन में रह रहे हैं, दोबारा
 अदालत करने कान्कनी शहरी प्राथमिक
 स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने
 डॉक्टरों के सामने दिए गए वीडियो बयान
 में बताया कि कथी दो माह पहले हुए
 थे।

सुदुर अस्पताल की बदहाली पर



स्वास्थ्य केन्द्र और उस समय उनकी बूढ़ श्रुत २२३ थी। शंकर पासना का आरोप है कि उस समय स्वास्थ्य केन्द्र में मौजूद एक व्यक्ति ने सय्य को डॉक्टर बनाकर उनका इलाज किया और दवाइयां भी दीं। उन्होंने बताया कि दवा खाने के बाद उनका श्रुत नियंत्रित होने के बजाय और बढ़ गया। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि संबंधित व्यक्ति डॉक्टर नहीं, बल्कि अस्पताल का कर्मचारी था, जो डॉक्टर की अनुपस्थिति में मरीजों का इलाज करता था। मरीज ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के दौरान दी गई दवाओं की वजह से तो मरीज का नाम सही ढंग से दर्ज किया जाता है और न ही उस पर दिनांक लिखी जाता है, जिससे इलाज का कोई समुचित रिकॉर्ड नहीं रह जाता। वहीं,

वर्षों बाद थुरु हुआ जेलगोरा गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार, विधायक रागिनी सिंह ने किया निरीक्षण

नवपराशर/अलकहिदा। अलकहिदा क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांगों आखिरकार पूरी हुई। क्षेत्र का एकमात्र प्रमुख समुदायिक भवन जेनगौरा गेट्स हाउस के जर्ज होने के कारण आज लोगों को शायद- विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब भारत कोकिया काली लीमिटेड (बीसीसीएल) ने इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है। इसीया विधायक रागिनी सिंह के लगातार प्रयासों के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने इस जगहित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। गुरुवार को विधायक रागिनी सिंह स्वयं निर्माण स्थल पर पहुंची और चल रहे जीर्णोद्धार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अब तक हुए काम पर संतोषपूर्वक महत्वासा (साथ ही अधिकारियों) को कई महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि निर्माण कार्य ज्वज गुणवत्ता के साथ किया जाय। विधायक ने निदेश दिया कि गेट्स हाउस का निर्माण इस प्रकार हो कि क्षेत्र खर्च में क्षेत्रवासियों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों और यह भवन आज वाले कई वर्षों तक लोगों के काम आ सके। इस दौरान विधायक ने



बीसीसीडी अधिकारियों के साथ क्षेत्र में सुरक्षाविधाओं से जुड़े अन्य विषयों पर बीसीसीडी वार्डों की 37 वीं बैठक कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखते हुए आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा प्रार्थमिकता दी जाए और सभी कार्यों में समभावपूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। गुणा स्मिटी डरी से वातावरणीय विधायक रागिनी सिंह ने कहा, क्षेत्रवासियों की सुविधा और जाहजित मेरी सर्वोच्च प्रार्थमिकता है। वर्षों से जजर पड़े जेलगरो गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार शुरू होना क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत है। हमारा प्रयास रहेगा कि गेस्ट हाउस सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए एक

आदर्श स्थल बने जिनकी रक्षण के
समय संतोष सिंह, अखिलेश सिंह,
उमेश यादव, राजू किशोर
जैना, अभिषेक पांडेय, स्वरूप
भट्टाचार्य, मेवालाल रजक, बल्लू
रजक, अनिल पासवान, बेषेश्वर
बावडी, सुनील पासवान, राजू
पासवान, ममता साव, अनीता
चौधरी, नीलू देवी, राहुल सिंह सहित
बड़ी संख्या में स्थानीय लोग
उपस्थित थे जिन्होंने कार्य शुरू
होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का
माहौल है लोगों का कहना है कि
कार्य पूरा होने के बाद उन्हें एक
आधुनिक सुसज्जित और सुविधायुक्त
सामुदायिक भवन मिलेगा, जिसका
लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा।

सेप्टिक टंकी की जहरीली गैस बनी काल, 2 मजदूरों की मौत



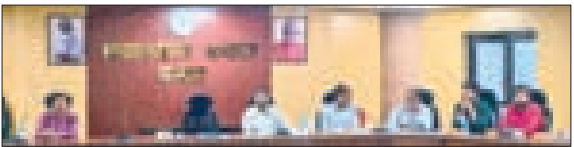
मनष्याऽ/मनबाऽ। मनबाऽ-गोमो रेलखं पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ गया। गोमा गौशाला के निकट रेलवे प्लेट पर पास पोस संख्या 284/18 पर के समीप एक अज्ञात व्यक्ति ने टिकी रोपे में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई जानकारी के अनुसार हादसे के समय इसी ट्रेक से राजधानी एक्सप्रेस को गुजरना था। पट्टरी पर पस पड़े होने के कारण ट्रेन को गोमो स्टेशन पर अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ट्रेकमैन ने मृत्युस्थल दिखाते हुए शिव को सूचना से हटायी,जिसके बाद राजधानी को आगे खलना किया गया। हट्टनी का सूचना पर आरपीएफ और कंस्टाबल थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पुलिस केक पंचनाम नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से संदर्भ कर शिनेशनकाक का प्रयास कर रही है फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला दुर्घटना का है या आत्महत्या का। पुलिस सेमि विदुओं पर जांच कर रही है।

धनबाद अंचल कार्यालय को व्यवस्थित व जनउपयोगी बनाएं - डीडीसी

कायावृत/भ्रमण/प्रतः अप विवास आयुक्त सन्नी रात्रि में गुरुवार को भ्रमण-अवसर कायावृत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उनसे कार्यालय की सुरक्षा एवं बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए वहादीदगारी के मर्यादितकरण का निर्देश किया। निदेश लागू की, परिसर में उम्बल्य थाना का उपयोग करने के अदरश में परिसर में अनुपयुक्त नदर में अदरश से दुदुनारी के निर्माण के लिए आदरशक जल करने का निर्देश दिया। दुदुनारी दुदुनारी दुदुनारी आयुक्त ने कहा कि भ्रमण-अवसर कायावृत परिसर का निरीक्षण विवास करने वाले हुए हैं सुरक्षा,दुवर्षित एवं जनउपयोगी बनाए निरीक्षण के दौरान कायावृत परिसर में स्थित अत्यंत ऊर्जर भवनों का भी अवलोकन किया गया। भवनों की स्थिति को देखते हुए उनको पुर्ननिर्माण,जीर्णोदर के लिए निर्देश/योजनाओं के अंगरगत प्रयास करने कर स्वीकृति की कार्यवाई करने की बात की।

समन्वयकों की लापरवाही पर डीडीसी सज्जी राज सख्त, दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

नवप्रदेश/धनबाद। धनबाद में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की योजनाओं में क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर विकास अयुक्त सन्नी राज ने उप विकास को जिला एवं सीपी प्रखंड-जल जीवन मिशन के समन्वयकों को कड़ी चेतावनी दी- उन्होंने कहा कि कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर नई टीम की नियुक्ति कर दी जाएगी। डीडिडीसी गुरुवार को समाहरणालय में स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर



रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रखंड समन्वयकों पंचायतों में सेग्रीगेशन शेड निर्माण की प्रगति की जानकारी मांगी, उपस्थित प्रखंड विवेक पदाधिकारियों ने बताया कि संबंध में समन्वयकों द्वारा कुछ कोई समन्वय ही नहीं किया गया। इस पर डीडीसी ने कड़ी नाराजता व्यक्त की।

व्यक्त की।
योजनाओं की बारीकी से हुई
समीक्षा.....

बैठक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट,सेनेटरी पार्क,सांसद आदर्श ग्राम योजना,पीएम जनमन, ओडीएफ प्लस,मॉडल कम्युनिटी सेनेटरी कॉम्प्लेक्स,मासिक धर्म

स्वच्छता प्रबंधन और धरती आवा
जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
सहित अन्य योजनाओं की प्रगति
की समीक्षा की गई। डीडीसी ने
जिला समन्वयकों को निर्देश दिया
कि वे प्रतिदिन प्रखंड समन्वयकों के
कार्यों की मॉनिटरिंग करें और सभी
लॉबिंग कार्यों को अविलंब पूरा
कराएं।

जल जीवन मिशन: 7 दिन में
निपटाएं लंबित मामले....

बैठक के दूसरे चरण में जल जीवन मिशन के तहत चल रही

योजनाओं, हर घर जल प्रमाण-पर की स्थिति और लॉबी कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई। इंडोर्स ने सभी कनीय अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे अपने काक्षेत्र में व्यापक सर्वे कर व सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित न रहे। जिन क्षेत्रों में हर घर जल प्रमाण-पर जारी करने के मानक पूरे नहीं हुए हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कर आले 7 दिनों के भीतर सभी लॉबी प्रमाण-पर जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक

कनीय अभियंता अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कर योजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति की सतत निगरानी रखें, ताकि निर्धारित समय-सीमा में जल जीवन मिशन के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। बैठक में पोपचरौड़ी-2 के कार्यपालक अभियंता मुरेश कुमार मंडल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुशांत मुरजौजी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, सभी प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर लोकतंत्र को लाटीतंत्र बनाने की कोशिश हो रही: रवि

आम नागरिकों, कॉलेज छात्रों और प्रगतिशील संगठनों से मार्च में शामिल होने का आह्वान

नव प्रदेश संवाददाता

कोडरमा। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में कारवाई, एनटीए को निरस्त करने एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल कर रहे छात्रों पर केंद्र की मोदी सरकार की पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से लाठी चार्ज और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ कोडरमा के आम नागरिकों की ओर से 25 जुलाई को झुमरीतिलैया में सुभाष चौक से झंडा चौक तक प्रतिवाद मार्च का

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा उपलब्ध कराई गई एंबुलेंस से सतगावां के मरीजों को मिल रही त्वरित स्वास्थ्य सुविधा

नव प्रदेश संवाददाता/सतगावां। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सतगावां को उपलब्ध कराई गई एंबुलेंस ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस एंबुलेंस के माध्यम से गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा अन्य आपातकालीन मरीजों को समय पर उच्च चिकित्सा केंद्र पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर और त्वरित इलाज मिल रहा है।करचेता निवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता राहुल कुमार ने बताया कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध होने के बाद स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है।अब जरूरतमंद मरीजों को समय पर रेफर कर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कई लोगों की जान बचाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह सेवा विशेष रूप से जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए भी काफी लाभदायक साबित हो रही है।इन्होंने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह एंबुलेंस सेवा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत है और इससे स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ एवं प्रभावी हुई हैं। ग्रामीणों ने भी इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि समय पर एंबुलेंस मिलने से आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को शीघ्र उपचार मिल रहा है।

6 माह से वेतन नहीं: आउटसोर्सिंग कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था ठप

श्रम अधीक्षक कार्यालय आज प्रदर्शन करेगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी : सीटू

नव प्रदेश संवाददाता कोडरमा। छह माह से मानदेय भुगतान नहीं होने के विरोध में झारखंड स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ (सीटू) के बैनर तले सदर अस्पताल व जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के पहले ही दिन जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं। एम्स-रे, अटल्ट्सोसोनग्राफी सहित कई जांच सेवाएं ठप रहीं, सफाई व्यवस्था चरमरा गई, मरीजों को टॉली तक उपलब्ध नहीं हो सकी और दवा वितरण भी प्रभावित रहा। समाहरणालय से निकले जुलूस ने सदर अस्पताल पहुंचकर धरना का रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने रमजदूरी की चोरी नहीं चलेगीइ और रकमाडो कंपनी होश में आओर जैसे नारे लगाए। सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान कर रही है, जबकि कंपनी को पूरी राशि मिल चुकी है। उन्होंने मानदेय भुगतान में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक बकाया मानदेय और निर्धारित वेतन का भुगतान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को श्रम अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा।

चंदवारा मे डीजल चोरी करते हाईवा चालक गिरफ्तार, 30 लीटर डीजल बरामद

नव प्रदेश संवाददाता/ चंदवारा। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष के निर्देश पर चंदवारा थाना की गश्ती टीम ने गुरुवार रैर रात ग्राम मंझलाडीह में कारवाई करते हुए हाईवा से डीजल चोरी करते एक व्यक्ति को रो हाथ गिरफ्तार किया है। चंदवारा थाना प्रभारी ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने एक हाईवा को संधिध अवस्था में खड़ा देखा। जांच के क्रम में बब्बू कुमार यादव नामक व्यक्ति हाईवा से डीजल निकाल रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे टीम ने पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से लगभग 30 लीटर डीजल, 3 प्लास्टिक जार और डीजल निकालने में प्रयुक्त रेंच बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बब्बू कुमार यादव, उम्र 21 वर्ष, पिता कारु यादव, साकिन सिंगारडीह, थाना जयनगर के रूप में हुई है। इस संबंध में चंदवारा थाना में कांड संख्या 58/26 दर्ज किया गया है। उस पर बीएनएस की धारा 303 (2) और 317(2) के तहत मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।

नीट पेपर लीक को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कांग्रेसियों द्वारा किया गया धरना-प्रदर्शन

महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से दिए गए ज्ञापन
नवप्रदेश संवाददाता

हजारीबाग : जिला कांग्रेस कमिटी के तत्वावधान में नीट पेपर लीक को लेकर लोकतंत्र बचाओ छत्र न्याय आंदोलन कार्यक्रम का आंदोल आयोजन कर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया । आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने की। मुख्य तीन मांगो पहला केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मंद प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। दुसरा परिक्षा में हुई अनियमितताओं एवं



उन व्यवस्थागत विफलताओं पर संसद में तत्काल चर्चा, जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य संकट में डाल दिया है तथा तीसरा नई दिल्ली में हुए संबंधित विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज सभी एकआईआर एवं अपराधिक मामलों को तत्काल वापस लिया जाए को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम ज्ञापन दिए गए । कार्यक्रम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय परिक्षा में

मोदी सरकार की पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से लाठी चार्ज और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ प्रतिवाद मार्च 25 को



आयोजन किया जा रहा है। इस मार्च में छात्र आंदोलन व उनकी मांगों के साथ संवेदना रखने वाले

सभी आम नागरिकों को मार्च में शामिल होने की अपील की गई है। उक्त जानकारी पूर्व छात्र नेता रवि

उत्कर्मित कन्या मध्य विद्यालय मरकच्चो में किया गया प्रबंधन समिति का पुनर्गठन

नव प्रदेश संवाददाता

मरकच्चो। प्रखंड अंतर्गत उत्कर्मित कन्या मध्य विद्यालय मारकच्चो में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन हेतु एक आम सभा का आयोजन गुरुवार को किया गया जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि रविशंकर सिंह एवं संचालन प्रभारी प्रधानाध्यापक कपिलदेव सिंह ने किया, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में परियोजना बालिका उच्च विद्यालय मरकच्चो के शिक्षक रामकृपाल सिंह उपस्थित रहे। विद्यालय में

भितिया में छोटकी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त ग्रामीणों ने प्रशासन से की पुल बनाने की मांग

नव प्रदेश विजय कुमार/चंदवारा (चंदवारा): चंदवारा प्रखंड अंतर्गत बंदी पंचायत के ग्राम भितिया में छोटकी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार, यह पुल भितिया सहित चौपारण के कई गाँव सहित बिहार के गया जी जिला के हजारों लोग इसी पुल से आवागमन का प्रमुख मार्ग है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, किसान तथा मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से पुल का शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत या नए पुल के निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की अपील की है, ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर, उपायुक्त ने दिए लक्ष्य आधारित कार्य के निर्देश

नवप्रदेश/गोड्डा। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अप्रैल से जून 2026 तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने गर्भवती महिलाओं का शन-प्रतिशन समय पर पंजीकरण, चार प्रसव पूर्व जांच (एएनसी), संस्थागत प्रसव तथा आयरन-फोलिक एसिड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बोआरीजोर और सुंदरपहाड़ी जैसे कमजोर प्रदर्शन वाले प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया। साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

कोडरमा में NIA का बड़ा ऑपरेशन: विस्फोटक मैगजीन हाउस और कारोबारी के घर छापा, 16 लाख नकदी व दस्तावेज मिलने की चर्चा

बांकुड़ा ब्लास्ट केस की जांच पहुंची कोडरमा, मैगजीन संचालक समेत दो गिरफ्तार, कई और ठिकाने NIA के रडार पर

नव प्रदेश संवाददाता

कोडरमा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा विस्फोट कांड की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कोडरमा जिले में बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की कोलकाता टीम ने नवलशाही थाना क्षेत्र के पुरनाडीह नवादा स्थित एक विस्फोटक मैगजीन हाउस और कोडरमा निवासी कारोबारी एवं मैगजीन संचालक शंकर यादव के आवास पर एक साथ छापेमारी की। सुबह से

कोडरमा में एनआईए की जांच के दौरान एक स्थान पर विस्फोटक सामग्री का पकड़ा जा रहा है।

चली कार्रवाई के दौरान टीम ने दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की गहन जांच की। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंदवारा पुलिस भी पूरे समय मौके पर तैनात रही। सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बाइक से विस्फोटक ले जाने के दौरान हुए विस्फोट, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी, उसकी जांच के क्रम में कोडरमा से जुड़े संभावित

जुलाई को सीजेपी के जंतर मंतर से संसद मार्च के आह्वान के बाद लाखों छात्रों के शांतिपूर्ण मार्च के दौरान केंद्र सरकार की पुलिस का विभत्स चेहरा उजागर हो गया।गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर लोकतंत्र को लाटीतंत्र बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार के छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक कारवाई से देशभर में आक्रोश है और छात्र,अभिभावक, आम नागरिक आक्रोशित है। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिसिया जुल्म के खिलाफ और केंद्र सरकार

छात्राओं को साइबर सुरक्षा व डायल 112 की दी जानकारी

कस्तूरबा विद्यालय में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के तहत जागरूकता कार्यशाला

करीब 25 सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता/पिता से 19 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार मीना देवी एवं किरण देवी हुईं, मतों के आधार पर किरण देवी अधिक मत प्राप्त

की छात्रों के आंदोलन पर तानाशाही रवैया के खिलाफ कोडरमा जिले के संवेदनशील आम नागरिक सड़को पर उतरकर विरोध जताएगी और छात्रों के आंदोलन को सशक्त बनाने का कार्य करेगी।इन्होंने कोडरमा जिले के सभी आम नागरिकों, कॉलेज छात्रों और प्रगतिशील संगठनों समेत छात्र आंदोलन के समर्थकों से प्रतिवाद मार्च में शामिल होकर चट्टानी एकता प्रदर्शित करने का आह्वान किया है।साथ ही राजनीतिक दलों से हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचने की अपील की गई है।

छात्राओं को साइबर सुरक्षा व डायल 112 की दी जानकारी

कस्तूरबा विद्यालय में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के तहत जागरूकता कार्यशाला

नव प्रदेश संवाददाता सतगावां। प्रखंड के पोखरडीहा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में गुरुवार को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को कानून, सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।कार्यशाला के दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को साइबर फ्राइम से बचाव के उपाय बताते हुए डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए डायल 112 के उपयोग और महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई।इस अवसर पर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 (बाल न्याय अधिनियम) के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया तथा बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई।थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह ने कहा कि आज के डिजिटल युग में छात्राओं को अपने अधिकारों, साइबर सुरक्षा और सुरक्षात्मक कानूनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवाएं संकट की घड़ी में सुरक्षा का मजबूत माध्यम हैं।कार्यक्रम में विद्यालय की वार्डन प्रतीक्षा मिंज, शिक्षिकाएं विनीता वखला, मंजू कुमारी,संजू कुमारी, वीना कुमारी, अमृता कुमारी, शिक्षक शक्ति कुमार, कल्याण कुमार, विमल किंडो सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं, कार्यशाला के अंत में छात्राओं ने अपनी जिज्ञासाओं से जुड़े प्रश्न पूछे, किनका पुलिस अधिकारियों ने वकता से उत्तर दिया। विद्यालय प्रशासन ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा के प्रति सजगता भी विकसित करते हैं।

आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इधर, कोडरमा के पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने पुष्टि की है कि एनआईए ने मैगजीन संचालक शंकर यादव के साथ उनके सहयोगी महेश कुमार मेहता को भी गिरफ्तार किया है। महेश डोमचांच थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव के निवासी हैं। एसपी के अनुसार, पूरे मामले के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं और एनआईए विभिन्न पहलुओं की गहन जांच कर रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि जिले के कुछ अन्य विस्फोटक मैगजीन हाउस भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, जिससे आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

एक नजर

मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चौपारण में बीएलओ-बीएलए की बैठक



नवप्रदेश/चौपारण। केबीएसएस उच्च विद्यालय, चौपारण में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बृथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं बीएलए-2 की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष (भाग-1) शारिक अख्तर उर्फ भुनु ने की। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड काग्रिस अध्यक्ष उपेंद्र यादव उर्फ गुलाबी यादव, अभिमन्यु प्रसाद भगत, पर्यवेक्षक रेवाली पासवान, बीरबल साहू सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने बीएलओ और बीएलए-2 से घर-घर जाकर अभियान चलाने, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।

18 दिनों में 1600 किमी की पदयात्रा, जगन्नाथ धाम पहुंचने वाले हैं सिंघरावां के मोहन



नवप्रदेश/चौपारण। आस्था, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए चौपारण प्रखंड के सिंघरावां निवासी मोहन कुमार पिछले 18 दिनों से लगातार पैदल तीर्थयात्रा पर हैं। अब तक वे करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए ओडिशा के पुरी पहुंचने वाले हैं। मोहन कुमार ने बताया कि उनकी यात्रा का आज 18वां दिन है। उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरूआत सिंघरावां से की थी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां तारापीठ में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद वे लगातार पैदल यात्रा करते हुए भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने बताया कि पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद भी उनकी यात्रा समाप्त नहीं होगी। वहां से वे पैदल ही विश्व प्रसिद्ध काणौर्फ सुनू मंदिर तक पहुंचने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान पुरी से करीब 10 किलोमीटर पहले सड़क पर उनकी मुलाकात संयोगवश चौपारण के पत्रकार विजय मेधेशिया एवं अन्य लोगों से हुई। अपने क्षेत्र के लोगों को अचानक सामने देखकर मोहन भावुक हो गए। वहीं पत्रकार विजय मेधेशिया और उनके साथियों ने मोहन की कठिन तपस्या, अटूट आस्था और साहस की सराहना करते हुए उनकी सफल एवं मंगलमय तीर्थयात्रा की शुभकामनाएं दीं। मोहन कुमार की यह पदयात्रा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी श्रद्धा, अनुशासन और दृढ़ निश्चय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प पर अडिग रहकर मोहन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची आस्था और मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

पेपर लीक के विरोध में झामुमो का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूँका



नव प्रदेश संवाददाता/कोडरमा : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) कोडरमा जिला समिति ने गुरुवार को जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय के नेतृत्व में केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और कथित पेपर लीक मामलों के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कार्यकर्ता झुमरी तिलैया के ब्लॉक रोड से जुलूस निकालते हुए झंडा चौक पहुंचे, जहां पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने केंद्र की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। जिला प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और उनमें निराशा का माहौल है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। कार्यक्रम में चंद्रदेव यादव, उमेश यादव, इफ्फान अंसारी, मोहम्मद अशरफ, दीपक विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे।

डोमचांच CO पर भ्रष्टाचार के आरोप, 27 जुलाई को धरने की तैयारी, SDO से मांगी अनुमति



नवप्रदेश/कोडरमा। डोमचांच अंचलाधिकारी रविन्द्र कुमार पाण्डेय पर भ्रष्टाचार और आम लोगों से कथित रूप से अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए स्थानीय नागरिकों ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सीपकर एकदिवसीय धरने की अनुमति मांगी है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन भूमि नक्शाने, दाखिल .खारिज सहित सामान्य राजस्व कार्यों के लिए भी लोगों को दलालों के माध्यम से मोटी रकम देनी पड़ती है। साथ ही कुछ भू-माफियाओं से साठगांठ कर गलत तरीके से कार्य कराने का भी आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के विरोध में 27 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोमचांच अंचल कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रस्तावित है। आवेदन पर संजय मेहता, मनोज रजक, अंगलाल मेहता, जीतू कुमार, विक्रम मेहता, सोनू कुमार सहित कई स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर हैं।

दिव्यांग बोर्ड शिविर में 5 लोगों को मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र

नवप्रदेश/कोडरमा। सदर अस्पताल कोडरमा में गुरुवार को आयोजित दिव्यांग बोर्ड शिविर में कुल 11 मरीजों की जांच की गई। चिकित्सीय परीक्षण के बाद 5 लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया। इनमें 2 अस्थि दिव्यांग, 1 सेरेब्रल पाल्सी एवं 2 मानसिक दिव्यांगता श्रेणी के लाभार्थी शामिल हैं। वहीं गुणा .बहरा श्रेणी के 4 आवेदकों को सुनने की क्षमता की विश्रुत जांच के लिए सदर अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रमण कुमार, जिला बीबीडी पदाधिकारी सह डिजिटिशन डॉ. मनोज कुमार, ईनटी विशेषज्ञ डॉ. प्रेमनाथ सिंह, ऑडियोलॉजिस्ट मनोज कुमार, कार्यालय सहायक अजीत कुमार तथा अनीश कुमार उपस्थित रहे।

राजकीय मध्य विद्यालय बिचारिया नईटांड में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन

नव प्रदेश संवाददाता/ मरकच्चो। प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बिचारिया नईटांड में गुरुवार को पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित शिक्षक विद्या सागर पासवान के देखरेख में प्रबंधन समिति का किया गया पुनर्गठन। जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में कुंदन शर्मा और उपाध्यक्ष के रूप में चिता देवी का चयन किया गया। चयन सर्व समिति से सभी 20 सदस्यों ने किया। इस मौके पर तेलोडीह पंचायत के मुखिया टिफिन पासी, पंचायत समिति सदस्य दीपक राम, पूर्व मुखिया तेलोडीह पंचायत मनिंदर राम, प्रधानाध्यापक अर्जुन महतो, शिक्षक सुनील साव, सीताराम रजक, महेश यादव, बनेश्वर यादव एवं अन्य गणमान्य अभिभावक गण उपस्थित रहे।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा : सम्राट चौधरी

नवप्रदेश/पटना। ठण्ण्ड पेपर लोक और छात्रों के मुद्दे पर बिहार की राजनीति गरमा गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लोक जैसे मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल



मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके भविष्य के साथ

अन्याय करने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का

भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर, छात्रों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की, जबकि सरकार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सीएचसी में एनएएम एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक, दिए कई दिशा निर्देश

नवप्रदेश/सूर्यपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सोरब प्रकाश कि अध्यक्षता में सभी एनएएम एवं सी एच ओ की बैठक की गई. बैठक में शामिल सभी को टीबी स्क्रीनिंग, एन सी ई स्क्रीनिंग एवं आर सी एच इंडी, भ्रूत्या पोर्टल, इंस्टीट्यूशनल डिलेवरी से संबंधित निर्देश दिए गए. मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद इरफान खान, स्वास्थ्य समन्वयक धनंजय कुमार सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, सोनू कुमार के साथ ही सभी एनएएम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे।



पत्रकारों को फिर मिले 50% रेल किराया रियायत!

बिहार विधान परिषद में गूंजा मुद्दा, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

नवप्रदेश/पटना। पत्रकारों को भारतीय रेलवे में मिलने वाली 50 प्रतिशत किराया रियायत को दोबारा लागू कराने की मांग अब बिहार विधान परिषद से केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। बुधवार को बिहार विधान परिषद में इस विषय पर गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि सदन द्वारा पारित इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि पत्रकारों को रेलवे किराए में मिलने वाली 50 प्रतिशत रियायत की सुविधा पुनः बहाल की जा सके। राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद अशोक कुमार पांडे ने संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि पत्रकारों को लगभग 45 वर्षों से यह सुविधा मिल रही थी।



वर्ष 2009-10 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस रियायत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था। इसके बाद वर्ष 2016-17 में रेलवे ने मान्यत प्राप्त पत्रकारों को रियायती पास पर ई-टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान यह सुविधा बंद कर दी गई, जिसे आज तक बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को लगातार यात्रा करनी पड़ती है, ऐसे में इस रियायत का बंद होना उनके लिए

बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। इसलिए इसे जल्द से जल्द पुनः लागू किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, सचिव दया शंकर तिवारी और संगठन सचिव बाल कृष्ण ने संयुक्त रूप से खुशी जताते हुए कहा कि यह उनकी लंबे संघर्ष की पहली बड़ी सफलता है।

उन्होंने कहा कि जब तक पत्रकारों को रेलवे रियायत संबंधी आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

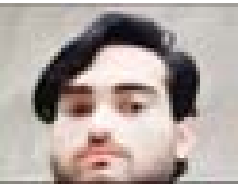
शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अजर अमर है : राघवाचार्य महाराज

नवप्रदेश/मधुबनी। बगहा अनुमंडल अंतर्गत मधुबनी प्रखंड स्थित राजकीय कृत हरदेव प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पंभरत उपाध्याय ने बताया कि मेरे पूर्व प्रधानाचार्य पंडित सुधाकर मिश्र जी के निवास स्थान चन्दौदा में श्रीमद भागवत कथा महायज्ञ में परम्पू जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से अमृत कथा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आजकी कथा में श्रेष्ठ विद्वान राघवाचार्य जी ने कहा कि श्रीमद भागवत कथा श्रवण से मनुष्य के जीवन का कल्याण होगा। मनुष्य प्रत्येक क्षण को मूल्यवान मानते हुए यदि सत्य, प्रेम, सेवा और परिश्रम को अपना जीवन मंत्र बना ले तो उसका जीवन स्वयं के लिए अनंद का स्रोत और समाज के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। भगवत गीता के अनुसार शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है।

इसलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह नहीं बल्कि आत्मज्ञान सत्य कर्षणा और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। इस अवसर पर डॉ वेद प्रकाश मिश्र, प्रधानाचार्या श्रीमती संगीता मिश्रा, रजनीकांत मिश्र, दिनेश कुमार गुप्ता, डॉ बालमुकुंद मिश्र, महेश मिश्र, वितरंजन तिवारी, दिनेश पति त्रिपाठी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों एवं हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

युवक की गला रेतकर हुई निर्मम हत्या, शव के पास मिला धारदार चाकू

नवप्रदेश/बेतिया। स्थानीय मनुआपुलथाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या हो जाने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान,असलम हुसैन,उम्र 20वर्ष,पिता, जाकिर हुसैन के रूप में की गई है। मृतक गौनाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है।बेतिया मेंअपने नाना के घर मेहंदियाबाड़ी में रहता था।श्रीनगर के सरकारी विद्यालय के पास सड़क के किनारे लहूलहान स्थिति में पड़ा हुआ मिला. मृतक राजमिस्त्री का काम करता था.वह प्रेम विवाह किया हुआ था.जोअपने नाना के घर रहकर मिस्त्री का काम करता था।परिजनों में संवाददाता को बताया किअभी हाल ही मे उसकी शादी.प्रेम विवाह से हुई थी।लड़के के परिवार वाले इस विवाह से खुश नहीं थे.इसके पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट की गई थी.इस कारण उसका हाथ टूट गया था पटना की सूचना मिलते ही मनुआपुल थाना प्रभारी, रवि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने हेतु जांच शुरू कर दी।पुलिस ने संवाददाता को बताया कि मृतक के शव के पास से एक धारदार चाकू बरामद हुआ है।प्रारंभिक जांच में युवक की चाकू गोद कर, गला रेतकर हत्या किए जाने की बात सामनेआई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया सरकारी मेडिकल कॉलेजअस्पताल कर जांच में जुड़ गई है.पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है।पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.घटना के कारणों के साथ-साथआरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मृतक के पिता ने संवाददाता को बताया कि युपी के पिता मैनूदीन खान भाई शाहिद खान उर्फ धोनी औरअन्य परिजनों ने मिलकरअसलम चाकू से गोदकर,गला कर हत्या कर दी है.उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही दोषियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है।



नवप्रदेश

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा : सम्राट चौधरी

नवप्रदेश/पटना। ठण्ण्ड पेपर लोक और छात्रों के मुद्दे पर बिहार की राजनीति गरमा गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लोक जैसे मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल



मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके भविष्य के साथ

अन्याय करने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का

पारिवारिक विवाद में विवाहिता ने की आत्महत्या

नवप्रदेश/बेतिया। विवाहिताओं का आत्महत्याकरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है,विविधा भी स्थिति विशेष मेंआत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रही है।दहेज प्रताड़ना,पति- पत्नी विवाद,सास,ननद बहु विवाद,पति प्रेमप्रसंग का विवाद इत्यादिअनेक विवादों में उलझने के कारण विवाहिता आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रही है। इसी क्रम में संवाददाता को पता चला है कि,बलथर थाने के छोटका धनकोटवा गांव में पारिवारिक विबाद में विवाहिताआशा देवी, उर्फ लक्खी देवी,उम्र 20 वर्ष फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतिका राजेश्वर बैठा उर्फ भागड़ बैठा की पत्नी बताई गई। उसका पति चंडीगढ़ में मजदूरी का काम करता है। घटना के बाद ग्रामीण, परिजन घर छोड़कर फरार हो गए,पुलिस को विवाहिता का नाम,पता की जानकारी लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।थानाअध्यक्ष,ओमप्रकाश सिंह ने संवाददाता को बताया कि घटना स्थल पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने संवाददाता को बताया कि घर पर सास लालपरी देवी, ससुर,प्रमोद बैठा,अपनी बेटियों के साथ धान की रोपनी करने खेत में चले गए थे,शाम में जब घर पहुंचे तो विवाहित आशा देवी,फूस के घर में लगे बांस से साड़ी से लटक देखा और मचाने लगे।घटना के बाद घर वाले और पड़ोसी इधर छोड़कर फरार हो गए थे।

पानी के छींटे से शुरू हुआ विवाद, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली

नवप्रदेश/मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के जजवार गांव में मामूली कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई। बाइक से पानी का छींटा पड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक की पहचान जजवार निवासी आशीष कुमार ठाकुर के रूप में हुई है, जिसका एस्कैमसीएच में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि आशीष कुमार ठाकुर मुंबई में नौकरी करता है और करीब एक माह पहले अपने घर आया था। घटना के दिन वह बाइक से अपने एक दोस्त को लेने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बाइक से पानी का छींटा पड़ने पर कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। आशीष ने बताया कि उसने तुरंत माफ़ी मांग ली थी और वहां से आगे बढ़ गया।आरोप है कि इसके बाजूद बदमाशों ने उसका पीछा किया। बारिश के कारण रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार हमलावर दो अपाचे बाइक पर सवार थे, जिनमें एक नीले और दूसरी लाल रंग की थी। उनकी उम्र करीब 21 से 22 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।



छपरा में गणित शिक्षक गिरफ्तार: नाबालिग छात्रा से अश्लील चैटिंग और छेड़खानी का आरोप

नवप्रदेश/छपरा। बिहार के छपरा शहर के एक निजी विद्यालय में कार्यरत गणित शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील चैटिंग करने और आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने का गंभीर आरोप लगा है। घटना सामने आने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही भगवान बाजार थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार शिक्षक की पहचान इमाम राजा के रूप में हुई है। वह सारण जिले के इसूपुर थाना क्षेत्र के असांव गांव का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में छपरा शहर के कटहरी बाग इलाके में किराये के मकान में रह रहा था। वह पिछले चार वर्षों से शहर के एक निजी विद्यालय में गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत था।पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी शिक्षक लंबे समय से पढ़ाई के बहाने छात्रा को परेशान कर रहा था। वह कथित तौर पर गणित में फेल करने की धमकी देकर छात्राओं पर दबाव बनाता था और उनका मोबाइल नंबर लेकर इंटरग्राम व व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश तथा आपत्तिजनक तस्वीरें भेजता था। छात्रा द्वारा विरोध करने पर उसे इराने-धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी विद्यालय में अपना नाम केवल हरजाहर बताता था, जिससे उसकी वास्तविक पहचान कल लोगों को नहीं थी। उनका कहना है कि करीब एक माह पहले छात्रा ने विद्यालय के प्राचार्य से भी शिक्षक की शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिक्षक कुछ छात्राओं को अकेले में अपने निजी कमरे में बुलाता था और अनुचित व्यवहार करता था। हालांकि, इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है।

स्कूल के गेट पर कूड़े का पहाड़, बदबू के बीच पढ़ रहे नौनिहाल

बारिश में कचरा सड़ने से संक्रमण का खतरा

नवप्रदेश/कोईलवर (भोजपुर)। कोईलवर प्रखंड के कायमनगर उर्दू विद्यालय के मुख्य द्वार पर जमा कचरे का ढेर बच्चों की सेहत और स्वच्छता व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़ा कर रहा है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं को रोजाना कूड़े, जलजमाव और सड़ांध के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश के बाद कचरा सड़ने से उठ रही तेज दुर्गंध ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जिस विद्यालय के परिसर में बच्चों को स्वच्छ वातावरण में शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके मुख्य द्वार पर ही गंदगी का अंबार लगा है। कई दिनों से कचरा जमा रहने के कारण विद्यालय के आसपास मक्खियों और मच्छ्यों



का प्रकोप बढ़ गया है। इससे डेंगू, मलेरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। छोटे-छोटे बच्चों को इसी गंदगी के बीच से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। कचरे से उठ रही बदबू का असर विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर भी पड़ रहा है। छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक और स्थानीय लोग भी इससे परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरा उठाव की

नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने कूड़े का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के दुकानदार भी यहां कचरा फेंक देते हैं। लोगों का कहना है कि विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश द्वार पर पसरी गंदगी जिम्मेदार विभागों की स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोल रही है। बारिश के मौसम में कचरा और जलजमाव संक्रमण फैलने का

कारण बन सकता है। इसके बावजूद कई दिनों से सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। नागरिकों ने पंचायत और संबंधित अधिकारियों से तत्काल कचरा हटाने और नियमित सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की है। कायमनगर पंचायत के स्वच्छता पर्यवेक्षक गणेश पाठक ने बताया कि विद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है। आसपास के दुकानदार कचरा फेंक देते हैं। मामले की जांच कर जल्द सफाई कराई जाएगी। प्रखंड स्वच्छता पर्यवेक्षक संतोष कुमार ने बताया कि विद्यालय के आसपास दुकानदारों द्वारा कचरा फेंका जाता है। समय-समय पर सफाई कराई जाती है।

एक नजर

छात्र आंदोलन पर बल प्रयोग लोकतंत्र के लिए

खतरा, केंद्र सरकार तानाशाही रवैया छोड़ें: संतोष

नवप्रदेश/सासाराम। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बिहार प्रदेश मुख्य जोन प्रभारी एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी संतोष कुमार ने छात्र आंदोलनों पर बल प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों के बुनियादी मुद्दों को लेकर किए जा रहे शान्तिपूर्ण धरना-प्रदर्शन पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और यह तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक है। संतोष कुमार ने कहा कि दुनिया के इतिहास में कोई भी शासक तानाशाही के बल पर लंबे समय तक टिक नहीं सका। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सभी समुदायों, मंडलाओं, छात्रों और अल्पसंख्यकों को समाज अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जब देश के शिक्षा मंत्री की बेटी विदेश में पढ़ती हो तो उन्हें देश के छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के बजाय सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में लगी हुई है। बसपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री छात्रों की समस्याओं पर संवाद स्थापित करने के बजाय उनके साथ कठोर रवैया अपना रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।



भाजपा नेता डॉ.मनीष पर हुए जानलेवा हमले की एनडीए कार्यकर्ताओं ने की कड़ी निंदा

नवप्रदेश/बिक्रमगंज। बिहार के पटना में दो अलग-अलग हिंसक घटनाओं के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायकों पर उग्र छात्रों के भीड़ ने जानलेवा हमला कर उन्हें निशाना बनाया। इसी क्रम में बुधवार को शाम करीब 6 बजे घंटित घटना में नीट पेपर लोक के विरोध में वामपंथी छात्र संगठन



(आईसा) ने नीट छात्रों के साथ उग्र प्रदर्शन करते हुए आयकर विभाग बेली रोड़ स्थित भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह काराकट विधानसभा नेता डॉ.मनीष रंजन की गाड़ी पर पथराव और जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान सैकड़ों झुंड में छात्रों ने भाजपा नेता उसके झुंडर के उपर छड़ के रड़ से पिटाई भी किया। जिस कारण में बेलैन् ग्राड़ी को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन घायल अवस्था में भी काराकट विधानसभा भाजपा नेता डॉ. मनीष रंजन के जखमी चालक गड्ड यादव ने आत्म-फनन में ग्राड़ी को वहां से हाई कोर्ट परिसर में भगाते हुए ग्राड़ी में सवार अन्य लोगों सहित अपनी जान बचाई। जबकि ग्राड़ी में सवार करीब तीन लोगों ने राजनीत औपधालय हाई कोर्ट अस्पताल में पहुंच चिकित्सक द्वारा अपना प्राथमिक उपचार कराया। जहां इलाज कर रहें डॉक्टरों ने सभी जखमी लोगों को खतरे से बाहर बताया। दूसरी तरफ इस हमले की सूचना मिलते ही भाजपा और एनडीए समर्थित कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए बताया कि यह महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने छात्रों के आंदोलन की आड में घुसकर उपद्रव फैलाया। जिसके लिए कोबिग छात्रों और असामाजिक तत्वों को भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और सैकड़ों कंटेंट किएटरर्स का सहारा लेते हुए भीड़ जुटाकर हिंसा भड़काई गयी है। जिस घटना को अंजाम देने के लिए बिहार में महागठबंधन की सोची समझी साजिश थी। हालांकि इस घटना मामले में स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को निश्चित करने में जुट गई है।

सुगौली में देसी कट्टा के साथ दो युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

नवप्रदेश/मोतिहारी/सुगौली। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बेलईट गांव में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया और उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया।थानाध्यक्ष अनिश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि बेलईट गांव में दो युवक अवैध हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। पुलिस टीम के पहुंचते ही दोनों युवक भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया।गिरफ्तार युवकों की पहचान नौवाडीह वाई संख्या-3 निवासी 19 वर्षीय रोहित कुमार और 20 वर्षीय सूरज कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान रोहित कुमार की कमर से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया।बुधवार को सदर डीएसपी दिलीप कुमार सिंह ने सुगौली थाना पहुंचकर मामले की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बरामद हथियार की जांच कराई जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहाँ से लाला गया तथा उसका इस्तेमाल किन घटनाओं में किया गया। पुलिस आरोपितों के आपराधिक इतिहास और अन्य मामलों में संभावित सलिप्तता की भी जांच कर रही है। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।



टीबी मुक्त भारत अभियान को मिली रफ्तार, पश्चिम चम्पारण में 183 मरीजों को मिली पोषण पोटली

नवप्रदेश/बेतिया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पश्चिम चम्पारण जिले में गुस्वारा को 183 टीबी मरीजों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने मडौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में 14 मरीजों को स्वयं पोषण पोटली प्रदान कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।इस दौरान डीएम ने कहा कि टीबी पूरी तरह उपचार योग्य बीमारी है। नियमित दवा, पोष्टिक आहार और चिकित्सकीय निगरानी से मरीज जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। उन्होंने मरीजों को दवा का पूरा कोर्स करने, प्रोटीनयुक्त भोजन लेने और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या पर तुरंत चिकित्सकों से संपर्क करने की सलाह दी। डीएम ने कहा कि टीबी संक्रमण की रोकथाम के लिए मरीज के परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच कराना आवश्यक है। साथ ही मास्क का उपयोग, खांसते-छीकते समय सावधानी और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी टीबी मरीजों का नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए, दवा सेवन की लगातार निगरानी हो तथा उपचार के दौरान आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त कजले वैभव नितिन, सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी एवं चिकित्सक मौजूद रहे।

पिपरासी थाना का एसपी ने किया औचक निरीक्षण, लॉबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश

नवप्रदेश/बगहा। बगहा पुलिस जिला के पुलिस अधीक्षक ने गुस्वारा को पिपरासी थाना का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण एवं लॉबित मामलों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के विभिन्न अभिलेखों, लॉबित कांडों, थाना परिसर की साफ-सफाई तथा अनुसंधान कार्यों का गहन जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने लॉबित कांडों के त्वरित निष्पादन पर विशेष बल देते हुए पुराने मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया। साथ ही थाना अभिलेखों एवं सचिवकओं का सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करने तथा अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना स्तर पर पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी एवं ज़ोन्सुन्धी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ शालीन एवं सम्मानजनक व्यवहार पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।



संक्षिप्त खबरें

कनॉट प्लेस की सभी दुकानों को बंद करने की अपील

नई दिल्ली। नई दिल्ली व्यापार संगठन (एनडीटीए) ने गुरुवार को कनॉट प्लेस की सभी दुकानों और दफ्तरों को गंभीर हालात के कारण गुरुवार शाम 6.30 बजे तक बंद करने की अपील की। संगठन का कहना है कि नई दिल्ली नागरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष केशव चंद्रा और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह षहल ने टेलीफोन से इसकी सलाह दी है। नई दिल्ली व्यापार संगठन (एनडीटीए) ने आदेश जारी कर कहा कि कनॉट प्लेस की खराब स्थिति के कारण से सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और दफ्तरों को 6.30 बजे बंद कर दिया जाए। संगठन ने सभी व्यापारियों और संचालकों से पूर्ण सहयोग की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री ने गुजरात में भारी बारिश को लेकर

मुख्यमंत्री को दिया हरसंभव सहायता का आश्वासन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। गुजरात सरकार के सूचना विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री ने राज्य में लगातार हो रही भारी वर्षा के बीच राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा कहा कि प्रभावित लोगों की सहायता और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत कर राज्य में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। गृह मंत्री शाह ने गुजरात को इस संबंध में हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भरपूर आश्वासन दिया।

छात्रों के प्रदर्शन पर अन्ना हजारे ने केंद्र से संवाद की अपील की

अहिल्यानगर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर केंद्र सरकार से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने के बजाय उससे बातचीत की जानी चाहिए और जवाबदेही तय करना ही सुशासन की पहचान है।महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में गुरुवार को अन्ना हजारे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक दो घंटे का मौन आंदोलन किया। इसके बाद वे अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में हजारे ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कथित पुलिस कार्रवाई को बेहद दुःखद बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टकराव नहीं, बल्कि संवाद सबसे प्रभावी समाधान है।

सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके की तबीयत खराब

नई दिल्ली। सोशल मीडिया अभियान कॉन्करोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके की गुरुवार को तबीयत खराब हो गयी। उनको तेज बुखार है। यह जानकारी खुद दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। दीपके ने लिखा, "पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार और शरीर में तेज दर्द है लेकिन अभी तक दर्द की दवा लेकर मैं काम चला रहा हूं। अगर आज आप मुझे जंतर-मंतर पर न देख पाएं तो माफ कीजिएगा। मुझे ठीक होने के लिए कुछ घंटे आराम करने की जरूरत है। शाम तक मैं विशेष-प्रदर्शन वाली जगह पर वापस आ जाऊंगा।

सिविकम सुरंग त्रासदी के बाद चार दिन चला खोज

एवं बचाव अभियान समाप्त, सभी 25 शव बरामद

नाम्ची। नामची जिले के झोलुंगे अंतर्गत समरदुंगा में निर्माणधीन नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की तीसरा स्टेशन-6 जलविद्युत परियोजना की सुरंग में पिछले चार दिनों से चलाया जा रहा खोज एवं बचाव अभियान गुरुवार को समाप्त हो गया। सुरंग से सभी 25 पीड़ितों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नामची जिला प्रशासन के अनुसार आज के बचाव अभियान के दौरान तीन और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही इस हादसे में मृतकों की कुल संख्या 25 हो गई। इसके बाद बचाव दल ने सुरंग का विस्तृत निरीक्षण किया और लापता सभी श्रमिकों के विवरण का मिलान करने के बाद पुष्टि की कि अब सुरंग के भीतर कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं है। मृतकों में एनएचपीसी लिमिटेड, एआरएक्स और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हैं। वे भारत के 10 राज्यों के निवासी थे, जिनमें पश्चिम बंगाल के 11, झारखंड के 4, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के 2-2 तथा केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पंजाब और असम के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं।

नेपाल में शिक्षा मंत्री के खिलाफ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग

काठमांडू। नेपाल के शिक्षा मंत्री सत्तमत पोखरेल के खिलाफ आज विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नारेबाजी और प्रदर्शन करने वाले पांच लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शिक्षा मंत्री पोखरेल गुरुवार को विश्वविद्यालय के 67वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काँतिपुर पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर मंत्री पोखरेल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे पांच लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। काठमांडू जिला पुलिस परिसर के 67वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काँतिपुर पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर मंत्री पोखरेल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे पांच लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। काठमांडू जिला पुलिस परिसर के एसीपी पवन कुमार भट्टराई ने इसकी पुष्टि की। प्रदर्शन में शामिल युवा स्नेपो बेबी मुदाबांदर और रमेरिटोक्रंसी लागू करीर जैसे नारे लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही अन्य शीर्ष नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को याद किया। नेताओं ने कहा कि आजाद का जीवन त्याग, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करत हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के एक चमकते हुए प्रतीक के रूप में, उन्होंने असाधारण साहस और देश के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण पेश किया। उनके जीवन ने अनगिनत युवा भारतीयों को मातृभूमि की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा दी। उनकी अमिट विरासत पीढ़ियों तक देशभक्ति की भावना को जगाती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंद्रशेखर आजाद को भावपूर्ण नमन करते हुए कहा कि देश के लिए समर्पित उनका संपूर्ण जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि की स्वतंत्रता को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया और अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस से आजाद ने ब्रिटिश हुकूमत को स्पष्ट संदेश दिया कि देश के संसाधनों पर अधिकार केवल देशवासियों का है। अमित शाह ने यह भी कहा कि आजाद ने क्रांतिकारियों की ऐसी पीढ़ी तैयार की, जिसने विदेशी शासन की नींव हिला दी।

भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा- कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि का निलंबित किये जाने को न्यायोचित ठहराया है और कहा है कि पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ आतंकवाद को राज्य की नीति में पोषित कर सिंधु जल संधि को बुनियादी भावना को ही खम कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में आयोजित प्राकृतिक संसाधनों का शासन: शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि की बुनियाद विषय पर उच्च स्तरीय खोज बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान पर सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सिंधु जल संधि पर देश का स्पष्ट खंड देहराया। हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करते हुए झूठी कहानी पेश करने की कोशिश की है।



उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीमा-पार आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में अपनाने वाले देश के साथ आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित सहयोग संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन देने से अलग कर-के नहीं देखा जा सकता। राजदूत पर्वतनेनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। यह संवैधानिक और कानूनी सच्चाई है जिसे पाकिस्तान

अनंतनाग हमले में पुलिसकर्मों की हत्या के बाद पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट

श्रीनगर। अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बुधवार दोपहर को हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल निगरानी बढ़ा रहे हैं, चेकपॉइंट्स को मजबूत कर रहे हैं और तलाशी अभियान चला रहे हैं।

इस बीच सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर ने कहा कि अनंतनाग में हुए आतंकी हमले

प्रधानमंत्री पेपर लीक की जिम्मेदारी लें : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाझ ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के सांसद खुद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सरकार बेहद कमजोर है, जो संसद नहीं चला पा रही।

प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि युवाओं की जायज मांगों के लिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हर उपलब्धि का श्रेय लेते हैं, चाहे मंगल ग्रह पर जाने का



के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया

है।कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों ने निगरानी

बढ़ा दी है, चेकपॉइंट्स को मजबूत किया है और तलाशी

अभियान शुरू किए हैं। नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षाबलों

प्रश्नपत्र चोरी, वितरण मामले में अब तक 45 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल: सीबीआई

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया कि नीट (यूजी) 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले की विस्तृत जांच के दौरान संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की सलिपता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्रश्नपत्र चोरी और उसके वितरण में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है तथा मामले में अब तक 45 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि वर्ष 2024 में बिहार पुलिस ने नीट (यूजी) परीक्षा का प्रश्नपत्र चोरी होने का मामला दर्ज किया था। उस समय प्रारंभिक स्टैडह के आधार पर संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को आरोपित बनाया गया था, क्योंकि उसका नाम अन्य परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलों में सामने आया था। बाद में यह मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच के दौरान प्रश्नपत्र चोरी,



उसके वितरण और उससे लाभान्वित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की गई। इस संबंध में पटना की सक्षम अदालत में 45 लोगों के खिलाफ कई आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं।

सीबीआई के अनुसार जांच के दौरान संजीव मुखिया की भूमिका

को लेकर भी विस्तृत पड़ताल की गई, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वह नीट-यूजी 2024 का प्रश्नपत्र चोरी करने या उसके वितरण में शामिल था। जांच के दौरान संजीव मुखिया फरार था। बाद में बिहार पुलिस ने उसे अन्य

मामलों में गिरफ्तार किया। चूंकि नीट-यूजी 2024 मामले की प्राथमिकी में भी उसका नाम था, इसलिए सीबीआई ने उससे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

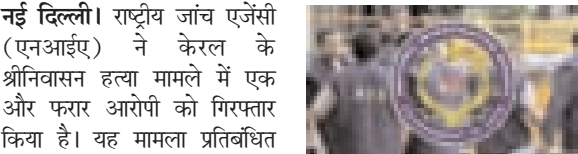
सीबीआई ने कहा कि जांच में उसकी सलिपता का कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण उसके खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। इसी वजह से उसे नीट-यूजी मामले में जमानत मिल गई। हालांकि, वह बिहार पुलिस द्वारा जांचे जा रहे अन्य मामलों में आरोपित होने के कारण न्यायिक हिरासत में बना रहा। नीट-यूजी 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले की गहन जांच पूरी कर ली गई है और साजिश में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया गया है। संजीव मुखिया को जानबूझकर बचाने या मामले से बाहर रखने संबंधी जो कथन अब प्रसारित किए जा रहे हैं, वे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे में निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन-मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन को मंजूरी 440 करोड़ रुपये होंगे खर्च



नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन और मिदनापुर के बीच 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 440 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क पर यात्री और मालगाड़ियों के परिचालन को अधिक सुगम बनाने के साथ-साथ माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह परियोजना भारतीय रेलवे की उच्च घनत्व वाले रेल मार्गों पर क्षमता विस्तार की योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बढ़ती यात्री और माल परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करना, परिचालन क्षमता में सुधार करना तथा उद्योगों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित तीसरी लाइन दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन से मिदनापुर तक 14.52 किलोमीटर लंबी होगी। यह खंड हाई स्पीटलाइजेशन नेटवर्क (एचयूएन-2) का हिस्सा है। वर्तमान में निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन-गोकुलपुर खंड एकल रेल लाइन है, जबकि इसके दोहरीकरण का कार्य पहले से जारी है। तीसरी लाइन बनने से इस रणनीतिक रेल मार्ग की क्षमता और परिचालन लचीलापन काफी बढ़ जाएगा। इस रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों के

साथ-साथ मैंगनीज, लौह अयस्क, कंटेनर, कोयला, क्लिंकर, पेलेट आयरन, इस्पात, गेहूं, पत्थर, स्लीपर, स्लैग, नमक, चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, चूना पत्थर, जिप्सम, उर्वरक, खाद्य तेल, सीमेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर परिवहन होता है। इस मार्ग पर वर्तमान में लगभग 23.80 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) माल ढुलाई होती है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड पर लाइन क्षमता का उपयोग 115.71 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जिससे यहां अत्यधिक दबाव की स्थिति बनी हुई है। तीसरी लाइन के निर्माण से इस भीड़भाड़ में कमी आएगी, यात्री और मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारु होगा तथा नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ेगी। परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर प्रतिवर्ष अतिरिक्त 3.52 मिलियन टन माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी। इससे कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को गति मिलेगी, परिचालन संबंधी बाधाएं कम होंगी तथा उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ मिलेगा। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना भारतीय रेलवे की क्षमता विस्तार और आधुनिक, दक्ष तथा भविष्य के लिए तैयार रेल नेटवर्क विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



वह उस समय सऊदी अरब के रियाद से भारत लौटा था। वह पिछले चार वर्षों से वहीं छिपा हुआ था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुहम्मदअली केपी के रूप में हुई है। वह पीएफआई के पलक्कड़ जिला अध्यक्ष था। एनआईए ने उसे गुरुवार यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया।

सरकार वार्ता को तैयार, आंदोलनकारी छात्र आवास या कार्यालय पर आए : नड्डा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को कहा कि जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इसके लिए छात्रों को उनके आवास या फिर कार्यालय आना होगा। संसद परिसर में जेपी नड्डा ने कहा, हां, हम तैयार हैं। हमारे घर या हमारे आधिकारिक कार्यालय आ जाइए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो दोषी हैं उन पर फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाकर कड़ी सजा दी जाएगी। हमारा कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि इस विषय का राजनीतिकरण ना करें। भागें मत, चर्चा कीजिए। कॉन्करोच जनता पार्टी के नेताओं ने 20 जुलाई को जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद बुधवार को देवबारा बातचीत के लिए आमंत्रित करने पर सीजेपी नेताओं ने कहा था कि वह उनके आवास या कार्यालय पर नहीं जाएंगे बल्कि किसी अन्य स्थान पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके पहले, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि आंदोलनकारी छात्रों से सरकार कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी और सीजेपी सूत्रों के मुताबिक वह सरकार से किसी भी तरह की बातचीत उनके ऑफिस या घर पर नहीं करेगी।



भारत का मानना है कि जिन परिस्थितियों में वर्ष 1960 में यह सिंधु हूँ थी, वे अब पूरी तरह बदल चुकी हैं।सूत्रों ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, आतंकवाद का, राज्य की नीति के रूप मेंप्रयोग खुद ही एक उल्लंघन है। भविष्य में यदि कोई भी समझौता या बातचीत की जाती है, तो वह आज की वास्तविकताओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर रिट्रैट, स्थानांतरण जल विज्ञान, बढ़ती मांग, नई तकनीक और सुरक्षा

समय तक संधि का सम्मान किया, वहीं पाकिस्तान के निरंतर सीमा पार आतंकवाद (संसद, मुंबई, उरी, पुलवामा और पहलगाम पर हमलों सहित) ने संधि के लिए आवश्यक आपसी विश्वास और पारस्परिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत का मानना है कि जिन परिस्थितियों में वर्ष 1960 में यह सिंधु हूँ थी, वे अब पूरी तरह बदल चुकी हैं।सूत्रों ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, आतंकवाद का, राज्य की नीति के रूप मेंप्रयोग खुद ही एक उल्लंघन है। भविष्य में यदि कोई भी समझौता या बातचीत की जाती है, तो वह आज की वास्तविकताओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर रिट्रैट, स्थानांतरण जल विज्ञान, बढ़ती मांग, नई तकनीक और सुरक्षा चिंताओं को प्रतिबिंबित करेगी। पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि में विवाद समाधान की स्पष्ट प्रक्रिया तय है, जिसकी शुरुआत के दो स्तर द्विपक्षीय

आधिकारिक स्तर की बातचीत से होती है, उसके बाद तटस्थ विशेषज्ञ और अंत में आवश्यकता होने पर मध्यस्थता न्यायालय का विकल्प आता है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने सीधे मध्यस्थता न्यायालय का रख अपनाकर संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया। भारत ने दोहराया कि वह न्यायालय ऋ-कानूनी तरीके से गठित किया गया था और इसका निर्णय भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। भारत का आरोप है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पाकिस्तान से बदलती परिस्थितियों - बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा आवश्यकताओं और आधुनिक तकनीक को देखते हुए संधि की समीक्षा और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर बातचीत से लगातार इनकार करता रहा। सूत्रों ने कहा कि यह संधि 1950 के दशक की परिस्थितियों और तकनीक पर आधारित थी, जबकि आज जल संसाधनों की जरूरतें और चुनौतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं।